नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 04 अप्रैल 2025 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 04 ■ पृष्ठ 12

JBT

जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून एवं करनाल से प्रकाशित

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

04 अमित शाह का बजा सियासी बिगुल | 11 मैच में रोहित और पंत पर रहेगी निगाह | 'राहु केतु' में काम करने के लिये उत्साहित है शालिनी 10

वक्फ संशोधन विधेयक को लाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श किया गया: रीजीजू

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहले सरकार और फिर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया और इसके जरिये वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाया गया है।

रीजीजू ने यह बात उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति देश में थीं और इनसे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपये की हुई, वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज तीन करोड़ रुपये बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। रीजीजू ने कहा कि किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने 2013 में इस कानून में संशोधन के लिए लाये गये विधेयक पर बनी जेपीसी और वर्तमान जेपीसी के कामकाज की तुलना करते हुए कहा कि उसकी तुलना में नयी समिति के सदस्यों की संख्या, बैठकों की संख्या, विचार विमर्श करने वाले राज्यों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिये वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं, वे निराधार हैं।

रीजीजू ने कहा कि विधेयक में जिस परमार्थ आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) की व्यवस्था की गयी है, उसका काम केवल यह देखना है कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाली जमीनों का प्रबंधन ठीक से हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक इकाई है और इसके मुतवल्ली की जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्ष किस्म की है, धार्मिक किस्म की नहीं। उन्होंने कहा कि इन अदालतों के मुताबिक, मुतवल्ली के ऊपर निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले 5 मार्च 2014 को उस समय की संप्रग सरकार ने आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन 123 मुख्य संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों या जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि विधेयक में अपील के अधिकार का प्रावधान किया गया है। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालतों में अपील कर सकता है।

खबर लिखे जाने तक राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा जारी रही।

> रीजीजू ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इसमें चार से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें तीन संसद सदस्य (सांसद) होंगे, 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त चार व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे उनमें दो महिलाएं होना जरूरी है। रीजीजू ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। इनमें तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक सांसद, एक विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले दो सदस्य, बार काउंसिल का एक सदस्य तथा राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। मुस्लिम समुदाय के चार सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है।

वक्फ विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया: कांग्रेस अध्यक्ष

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वक्फ विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि यह (विधेयक) अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। खरगे ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएं और सरकार इसे वापस ले ले। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 मत आए जबकि विपक्ष में 238 मत। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि इसमें खामियां और कमियां हैं तथा सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। खरगे ने कहा कि 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' की स्थिति उचित नहीं है और यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह दान से संबंधित विधेयक है लेकिन इसके प्रावधानों के जरिये अल्पसंख्यकों के हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है।

भारत और थाईलैंड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन किया: पीएम मोदी

बैंकाक। भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का गुरुवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी एवं नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथा विस्तारवाद के बजाय विकास की नीति में विश्वास करते हैं। मोदी ने यह टिप्पणी थाईलैंड की अपनी समकक्ष पैतोंगतार्न शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की।

मोदी ने शिनावात्रा के साथ हुई बातचीत के बारे में कहा कि हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है। हमने आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग (एमएसएमई), हथकरघा और हस्तशिल्प में सहयोग के लिए भी समझौते किए गए हैं। भारत और थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी की स्थापना को लेकर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लेकर संस्कृति तक के क्षेत्रों में पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। वार्ता के दौरान दोनों देशों की एजेंसियों ने मानव तस्करी और अवैध प्रवास से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। थाईलैंड ने हाल ही में म्यांमा में फर्जी नौकरी गिरोह के चंगुल में फंसे 549 भारतीय नागरिकों को वापस लाने में भारत की मदद की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने साइबर अपराध के शिकार भारतीयों की वापसी में सहयोग देने के लिए थाईलैंड सरकार का आभार व्यक्त किया। हमने इस बात पर सहमति जताई कि हमारी एजेंसियां मानव तस्करी और अवैध प्रवास से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगी। मोदी ने कहा कि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि आज हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच 'रणनीतिक वार्ता' स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान में एकता और केंद्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है। मोदी ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हम दोनों एक मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास करते हैं।

उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा करते हुए यह बात कही, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है और दक्षिण चीन सागर (एससीएस) तथा पूर्वी चीन सागर (ईसीएस) दोनों में ही क्षेत्रीय विवादों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपनी यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के 'रामायण' भित्ति चित्रों पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए थाईलैंड सरकार का आभारी हूं। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने उन्हें 'त्रिपिटक' भेंट किया। त्रिपिटक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रतिष्ठित संकलन है, जिसमें 108 खंड हैं।

संक्षिप्त खबरें

अब सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा SC की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा

नई दिल्ली। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा। एक अप्रैल को हुई फुल कोर्ट बैठक में सभी जजों ने यह फैसला लिया है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जजों को पदभार ग्रहण करने पर या जब भी उनकी संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण चीज जुड़ती है, तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को देंगे। खुद चीफ जस्टिस भी ऐसा करेंगे। इसके बाद इन संपत्ति के ब्यौरे की जानकारी सम्बंधित जज की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब तक चीफ जस्टिस समेत 30 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है।

दिल्ली सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करेगी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आयुष्मान भारत योजना में 'सबसे गरीब लोगों' को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को बताया कि योजना के तहत दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद आयुष्मान भारत योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, मरीजों को बेहतर प्राथमिक देखभाल मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे, जिससे बेहतर निगरानी और प्रबंधन हो सकेगा। सिंह ने कहा कि हम सबसे पहले उन लोगों को कार्ड जारी करेंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसमें एएवाई के तहत लाभार्थी और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं।

पुणेः ससून अस्पताल के 2 अधिकारियों के घर एसीबी का छापा, करोड़ों जब्त

मुंबई। पुणे के ससून अस्पताल के दो अधिकारियों के घर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को छापा मारकर करोड़ों रुपये जब्त किये हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। इन दोनों अधिकारियों को आज ही एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को पांच अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम ने बुधवार को ससून अस्पताल के अधिकारी सुरेश बनवले और जयंत चौधरी को 50-50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज सुबह एसीबी टीम ने इन दोनों अधिकारियों के घर पर छापा मारा। टीम ने जयंत चौधरी के घर से 39 लाख रुपये और सुरेश बनवले के घर से एक करोड़ 35 लाख 95 हजार रुपये और बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके बाद इन दोनों को पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को पांच अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी सूत्रों ने बताया कि ससून अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर

प. बंगाल में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, वेतन लौटाने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के करीब 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नियुक्तियां फर्जी तरीके से की गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया, उन्हें वेतन वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है जो दागी नहीं हैं। कोर्ट ने 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने सात मई 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह भर्ती प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है।

कोर्ट ने कहा था कि 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना अफसरों का काम है। पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में पढ़ाई ठप हो जाएगी। याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर बिना किसी भी हलफनामे और मौखिक दलील के आधार पर ही मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दीं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को शिक्षकों की भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24 हजार उम्मीदवारों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत लेकिन मानेंगे आदेश: ममता बनर्जी

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई, जिसमें राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार 753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार फैसले को मानते हुए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। बनर्जी ने कहा कि मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों का अत्यधिक सम्मान करती हूं लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, लेकिन जो भी कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, उन्हें आजमाया जाएगा। बनर्जी ने इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पहले ही जेल में हैं लेकिन भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और कर्मियों से मुलाकात करेंगी और उन्हें आश्वस्त करेंगी कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बनर्जी ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है और इस समय सीमा के अंदर वह इसे निश्चित तौर पर लागू करेंगी।

ट्रंप ने भारत पर 27 प्रतिशत का शुल्क लगाया, सरकार कर रही है प्रभाव का आकलन

वाशिंगटन/नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अपने उत्पादों का निर्यात करने वाले करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगा दिया है। इसी निर्णय के तहत भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया गया है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात तक के उत्पादों की बिक्री पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका ने भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 27 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है। हालांकि, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कुछ खनिज पदार्थ को इससे छूट दी गई है। ये उत्पाद अमेरिका में उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका ने भारत को अनुचित व्यापार व्यवहार का 'सबसे अधिक दुरुपयोग' करने वाला देश बताते हुए उसपर शुल्क लगाया है। अमेरिका को झींगा, कालीन, चिकित्सा उपकरण और सोने के आभूषण जैसे उत्पादों का निर्यात प्रभावित होगा। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मा के निर्यात को उसके प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त मिलेगी। ऊर्जा को शुल्क से छूट देने का मतलब यह भी होगा कि भारत अमेरिका को पेट्रोल जैसे ईंधन का निर्यात जारी रख सकता है। शुल्क से छूट प्राप्त सामान भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने इस शुल्क पर सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह घोषणाओं के 'प्रभावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है' तथा अमेरिकी व्यापार नीति में इस फैसले के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का भी अध्ययन करेगी। ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क पांच अप्रैल से और 27 प्रतिशत शुल्क नौ अप्रैल से प्रभावी होगा। यह 27 प्रतिशत शुल्क, अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर वर्तमान में लागू किसी भी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

हालांकि, इस कदम से अमेरिका को भारत की कुछ वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इनमें बांग्लादेश (37 प्रतिशत), चीन (54 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत) और थाइलैंड (36 प्रतिशत) शामिल हैं, जिन्हें बढ़े हुए शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे शुल्क का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की।

ट्रंप ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में कहा कि यह मुक्ति दिवस है, एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण। दो अप्रैल, 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका के भाग्य का पुनः उदय हुआ, और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना शुरू किया। हम इसे समृद्ध, अच्छा और समृद्ध बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाया गया शुल्क, अमेरिका पर लगाए गए शुल्क का आधा है। व्यापार और गैर-व्यापार बाधाओं और मुद्रा समायोजन को शामिल करने के बाद यह 52 प्रतिशत बैठता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4 प्रतिशत शुल्क वसूलता है, लेकिन थाइलैंड और अन्य देश इससे कहीं अधिक दरें 60 प्रतिशत, भारत 70 प्रतिशत, वियतनाम 75 प्रतिशत, तथा अन्य देश इससे भी अधिक दरें वसूल रहे हैं।

पिछले साल (2024 में) अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 46 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) था। प्रमुख फार्मा निर्यात को अभी छूट दी गई है, जबकि वाहन और कलपुर्जों पर कुछ दिन पहले ही 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

रक्षा मंत्री ने दिखाई माउंट कंचनजंघा और माउंट एवरेस्ट के लिए अभियान को हरी झंडी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंघा के लिए अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान में भारतीय सेना के 24 पर्वतारोही 10 एनसीसी कैडेट्स के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। इसी तरह भारतीय सेना और नेपाली सेना की संयुक्त टीम माउंट कंचनजंघा की चढ़ाई के लिए रवाना हुई है।

भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 10 एनसीसी कैडेट्स समेत 34 पर्वतारोही शामिल हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी के नेतृत्व में पारंपरिक साउथ कोल रूट का अनुसरण करेंगे। यह टीम माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर) पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराएगी। इसी तरह संयुक्त भारत-नेपाल अभियान का उद्देश्य माउंट कंचनजंघा पर चढ़ना है,

जिसमें भारतीय सेना के 12 पर्वतारोही और नेपाली सेना के छह पर्वतारोही शामिल होंगे। माउंट कंचनजंघा (8,586 मीटर) के लिए टीम का नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह करेंगे।

माउंट एवरेस्ट पर संयुक्त एनसीसी अभियान का नेतृत्व कर्नल अमित बिष्ट करेंगे। इस दल में पांच छात्राएं, पांच छात्र कैडेट्स, चार अधिकारी और 11 स्थायी प्रशिक्षक शामिल होंगे। इस महीने शुरू होने वाले इस अभियान का लक्ष्य मई तक अपने-अपने शिखरों पर पहुंचना है। रक्षा मंत्री ने पर्वतारोहियों से बातचीत के दौरान उनके साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प को सराहा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान में शामिल युवा अन्य युवाओं को प्रेरित करने के साथ ही उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में भारत का नेतृत्व करेंगे।

इन अभियानों को सशस्त्र बलों के असाधारण कौशल और अदम्य भावना को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए गए हैं। इनसे भावी पीढ़ियों को साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की भावना के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। भारतीय सेना के इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर पी शर्मा, नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल और अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए।

किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे: डल्लेवाल

चंडीगढ़। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने गुरुवार को कहा कि किसान अपना आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि राज्य की आप सरकार ने पुलिस कार्रवाई में शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं से प्रदर्शनकारियों को हटाकर उनके साथ 'विश्वासघात' किया है।

डल्लेवाल पिछले साल 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, ताकि फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करने की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने का केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। जनवरी में केंद्र द्वारा किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद डल्लेवाल ने खनौरी प्रदर्शन स्थल पर चिकित्सा सहायता लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया। गुरुवार को उन्हें पटियाला के एक निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाद में वह फरीदकोट जिले में अपने पैतृक गांव चले गए।

पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए डल्लेवाल ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तरफ सरकार के साथ बैठकें हो रही हों और दूसरी तरफ बैठक के बाद किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हो। डल्लेवाल ने कहा कि जिस सरकार ने हमें धोखा दिया है, वह आंदोलन को उखाड़ सकती है, लेकिन हमारा इरादा नहीं डिगा सकती।

ग्रेनो प्राधिकरण ने अवैध कालोनी पर चलाया बुलडोजर, 8 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम अच्छेजा में अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कालोनी काट रहे कालोनाइजरों पर आज बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने करीब 4 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। कालोनाइजर इस जमीन पर अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे।

अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज यानी बृहस्पतिवार को प्राधिकरण की टीम ने अच्छेजा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के ग्राम अच्छेजा के खसरा संख्या 1420 और 1421 की लगभग 4000 वर्ग मीटर जमीन पर रामायणम के नाम से विला बनाकर अवैध कालोनी बसाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर रोक लगाई गइ थी। इसके बावजूद कालोनाइजर चोरी-छिपे अवैध निर्माण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज एसडीएम जितेंद्र गौतम, तहसीलदार पुष्पा यादव, वर्क सर्किल-वन के प्रभारी रतिक, वर्क सर्किल दो के प्रभारी सन्नी यादव और वर्क सर्किल-3 के प्रभारी राजेश कुमार निम के साथ एसीपी बिसरख दीक्षा और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया।

एसीईओ ने बताया कि प्राधिकरण की टीम ने 6 जेसीबी और 2 डंपर की मदद से तीन घंटे में कार्रवाई संपन्न की। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपये से अधिक होने का आकलन है। एसीईओ ने अतिक्रमणकारियों को चेताया है कि अच्छेजा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में है। प्राधिकरण की अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इस तरह की अवैध कॉलोनियों में लोग अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

सबस्टेशन बदलने पर कनावनी गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन

आठ से 10 घंटे तक कटौती का लगाया आरोप

❖ जनभावना टाइम्स

ट्रांस हिंडन। कनावनी गांव के लोगों ने गुरुवार को सबस्टेशन बदलने के विरोध में नीतिखंड स्थित सबस्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि फीडर बदलने के बाद आठ से 10 घंटे की कटौती हो रही है।

कनावनी गांव को अभी तक नीतिखंड स्थित सबस्टेशन से आपूर्ति हो रही थी। पिछले दिनों विद्युत निगम से इसे शक्तिखंड चार सबस्टेशन से जोड़ दिया। सबस्टेशन बदलने से बिजली कटौती होने का आरोप लगा कई लोग नीतिखंड सबस्टेशन पहुंचे और प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग रखी कि आपूर्ति पहले की तरह ही की जाए। गांव निवासी सतीश नागर का कहना है कि करीब दो सप्ताह पहले सबस्टेशन बदला गया, जिसके बाद से रोजाना गांव में आठ से 10 घंटे कटौती हो रही है। विद्युतकर्मियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। प्रदर्शन करने वालों में ऋषि प्रधान, शुभम व नीरज आदि शामिल रहे।

जोन तीन के मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल का कहना है कि पुराना सबस्टेशन ओवरलोड था। गर्मी को देखते हुए बेहतर आपूर्ति के लिए यह कदम उठाया गया है। दो दिन पहले ही सबस्टेशन बदला गया है। इस दौरान लंबे समय के लिए आपूर्ति बाधित रही, जिसके बारे में लोगों को पहले से सूचना दे दी गई थी। दो सप्ताह से कटौती होने की बात गलत है। अब कनावनी में आपूर्ति सामान्य है।

संक्षिप्त खबरें

लोनी में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

लोनी। लोनी थाना पुलिस ने गिरी मार्केट कालोनी में तीन दिन पूर्व हुई विवाहिता की मौत के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। महिला का शव फंदे से लटका मिला था। खन्ना नगर कालोनी निवासी रेशमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आठ माह पूर्व बेटी मौज्जमा उर्फ हनी की शादी गिरी मार्किट निवासी मोहीन से की थी। शादी के बाद से ही बेटी का पति दहेज में दस लाख रुपये लाने के लिए आए दिन मारपीट करता था। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि हनी ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच पैसे लाने के लिए बोलने पर मारपीट हुई थी। जिसके बाद पत्नी ने फंदा लगा लिया था। डर के चलते पत्नी के परिजन को घटना की सूचना देकर वह फरार हो गया था। मोहीन को गिरफ्तार कर लिया है। वह मेडिकल स्टोर चलाता है।

उत्सव में डेढ़ हजार छात्र शामिल होंगे

गाजियाबाद। गुलधर स्थित आरकेजीआईटी संस्थान अपने 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में चार और पांच अप्रैल को टेक्निकल उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। संस्थान सलाहकार प्रो. लक्ष्मण प्रसाद और निदेशक डॉ. बीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सांस्कृतिक, साहित्यिक, हॉबी एक्टिविटीज और खेलकूद प्रतियोगिताओं में विभिन्न संस्थानों के लगभग डेढ़ हजार छात्र हिस्सा लेंगे। इस मौके पर डॉ.डीके चौहान, एचजी गर्ग, डॉ. आरके. यादव, डॉ. पुनीत, डॉ. रामेंद्र, आलोक त्यागी, प्रिया शर्मा, विकास त्यागी, डॉ. नीना शर्मा, वैभव शर्मा, प्रशांत राठी एवं डॉ. संजीव गोयल मौजूद रहे।

राष्ट्र सेविका समिति का शाखा संगम छह अप्रैल को

ट्रांस हिंडन। राष्ट्र सेविका समिति छह अप्रैल को शाखा संगम का आयोजन राजेंद्रनगर स्थित स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर में करेगी। कार्यक्रम शाम पांच बजे से साढ़े छह बजे तक चलेगा। इसमें समिति की विभिन्न शाखाओं की ओर से प्रदर्शनियां, घोष, योग, आत्मरक्षा, गीत एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन में सेविकाओं को एक-दूसरे से प्रेरणा लेने और संगठन के प्रति अपने भाव को और गहरा करने के साथ महिला शक्ति का सशक्त स्वरूप प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।

फर्जी आईडी बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा युवक

मुरादनगर। बीटेक छात्रा की फर्जी इस्टाग्राम आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी छात्रा के प्रोफाइल पर अश्लील फोटो लगाकर सहपाठियों व रिश्तेदारों के पास भी भेज रहा है। इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर की एक कॉलोनी निवासी युवती दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित एक कॉलेज में बीटेक की छात्रा है। छात्रा का आरोप है कि किसी ने उसके नाम की फर्जी इस्टाग्राम आईडी बना ली है। आरोपी है कि फर्जी आईडी के प्रोफाइल पर उसकी अश्लील फोटो लगा दी। आरोपी फर्जी आईडी से छात्रा के सहपाठियों व रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट भेज रहा है। जब आरोपी से छात्रा ने आईडी डिलीट करने को कहा तो उसने इंकार कर दिया।

ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित पुश्ता रोड पर ईंट के ओवरलोड ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन ने गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक सनी के भाई गांव फखरपुर जिला बागपत निवासी ओमकार की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ति की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। चालक को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में थाना लोनी बार्डर पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली सहारनपुर रोड से चेकिंग के दौरान एक शातिर मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक व तीन मोबाइल बरामद हुए हैं। एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को बाइक के साथ पकड़ा गया, उसकी पहचान दिल्ली निवासी रवि शर्मा के रूप में हुई है।

हवाई यात्रियों के गहने अनावश्यक रूप से जब्त न करे : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हवाई यात्रियों द्वारा पहने गए गहने सहित उनके पुराने आभूषण को हवाईअड्डों पर अनावश्यक रूप से जब्त न किया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ को सीमा शुल्क विभाग ने सूचित किया कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इस मामले में हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श कर रहा है। सामान नियम में संशोधन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इस पर पीठ ने यह निर्देश पारित किया। पीठ 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत आने वाले देश और विदेश के हवाई यात्रियों के सामान को जब्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। पीठ ने कहा कि क्योंकि सीबीआईसी व सीमा शुल्क विभाग अब सामान नियमों में संशोधन करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर रहे हैं। इसलिए सीमा शुल्क विभाग अपने सभी अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराए। पीठ ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक सामान नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो 19 मई तक एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए, जिसका नियमों में संशोधन होने तक सीमा शुल्क विभाग द्वारा पालन किया जाएगा।

छह अप्रैल को भाजपा मनायेगी स्थापना दिवस

❖ जनभावना टाइम्स

गाजियाबाद। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में होने वाले भाजपा के आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थापना दिवस की तैयारी के बाबत एक कामकाजी बैठक का आयोजन कवि नगर रामलीला मैदान स्थित जानकी सभागार में किया गया।

जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र शिशौदिया मौजूद रहे। बैठक में सभी महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री, प्रकोष्ठों विभागों के संयोजक सहित वरिष्ठ भाजपाई मौजूद रहे। बैठक में जानकारी देते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र शिशौदिया ने बताया यह सर्वविदित है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का तृतीय कार्यकाल भारत की राजनीति में विकास के परिवर्तन का नया युग लेकर आगे बढ़ रहा है। इस अप्रतिम कार्यकाल के मध्य ही इसी महीने में भाजपा का 45 वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है। यह कार्यक्रम *भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को जिला महानगर स्तर पर होगा।

सम्मेलन में 3 वक्ताओं का उदबोधन होगा। जिसमें भाजपा का चुनावी एवं संगठनात्मक विस्तार, भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन एवं प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के साथ 11 वर्षों में विकसित भारत की यात्रा विषयों से सम्बद्ध रहेगा।

मण्डल अध्यक्ष स्तर से ऊपर के सभी कार्यकर्ता (वर्तमान / पूर्व/वरिष्ठ) गाँव / शहर वार्ड में प्रवास करेंगे। साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य / सभासद, पार्षद सहित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी प्रवास करेंगे। प्रत्येक को पूरे दिन में कम से कम 4 घण्टे गांव, मोहल्ला या सेवा बस्ती का प्रवास करना है। सभी प्रवासियों को उनके करणीय कार्य बताते हुए कहा कि सभी को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मिलना और चर्चा करना। भाजपा कार्यकर्ताओं के संग भाजपा ध्वज लेकर गलियों में शोभयात्रा निकलवाना।सायंकाल ग्रामीणों व मोहल्ला निवासियों की चौपाल लगवाना। भाजपा के वरिष्ठ लोगों, आपातकाल सेनानी, व कारसेवको का सम्मान कराना। बूथ समिति की बैठक करना। प्रवास के समय मंदिर, अस्पताल, स्कूल गलियों में स्वच्छता अभियान कराना।

इन सभी आयामों के चलते भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली सहित अन्य आयाम पूरी तत्परता से जारी रहेंगे। बैठक में महापौर सुनीता दयाल, मानसिंह गोस्वामी, विधायक अजीत पाल त्यागी, बलदेव राज शर्मा, पूर्व महापौर आशु वर्मा, सरदार एसपी सिंह, पूर्व विधायक कृष्ण वीर सिरोही, विजय मोहन, पूर्व विधायक रूप चौधरी, अशोक मोंगा, अजय शर्मा, अशोक गोयल, अशोक नागर, अमरदत्त शर्मा, पृथ्वी सिंह कसाना, डॉक्टर वीरेश्वर त्यागी, राजेंद्र त्यागी, अनिल स्वामी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे।

गार्ड को हटाने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

❖ जनभावना टाइम्स

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-82 स्थित पॉकेट 7 में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह विवाद सोसायटी के एक सुरक्षाकर्मी को हटाने को लेकर हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसे पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंप दिया गया है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे के अनुसार, बीते दिनों सोसायटी में एक कार बिना उचित एंट्री के प्रवेश कर गई, और उस कार में सवार लोग एक साइकिल चोरी कर फरार हो गए। सुरक्षाकर्मी की लापरवाही के कारण उन्होंने उसे हटा दिया था। इसी बात को लेकर विरोधियों के बीच नाराजगी थी। बुधवार देर शाम, जब दुबे सोसायटी के गेट के पास गार्ड की कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे और उनसे झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते, एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस घटना में पूर्व अध्यक्ष एके सोलंकी, प्रतीक, कपिल, अजय श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ लोग अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। हमले के बाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मेडिकल परीक्षण भी कराया है। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं और सीने में तेज दर्द हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनकी जान लेने की नीयत से हमला किया था। राघवेन्द्र दुबे ने बताया कि घटना से पहले आरोपी पंकज झा ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर बुलाया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमला पहले से योजनाबद्ध था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुबह के समय अमितेश सिंह तलवार लेकर वहां पहुंचे थे, जिसका वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस से अपील की है कि इस जानलेवा हमले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

कर्मियों की वापिसी और वेतन की मुख्य अभियंता ने भी उठाई मांग

नोएडा। विद्युत निगम के संविदा कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर निकाले गए 33 कर्मियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग की है। इसके साथ ही वेतन कटौती का भी विरोध करते हुए पूर्व की भांति दिए जा रहे वेतन को पुनः बहाल करने की मांग की है। वहीं मुख्य अभियंता कार्यालय ने भी संविदा कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पीवीवीएनएल की एमडी को पत्र लिखा है। संविदा कर्मचारियों की मांगों की सिफारिश की है। दरअसल, बीते दिनों को विद्युत निगम में संविदा पर तैनात 33 कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिया गया था। इसके साथ ही संविदा के अन्य कर्मचारियों के वेतन में मासिक चार हजार रुपये की कटौती की गई। इससे संविदा कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके के चलते बीते दिनों संविदा कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था।

स्वस्थ लिवर, स्वस्थ जीवन विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण समिति (PFWS) द्वारा गुरुवार को पुलिस मुख्यालय (PHQ) स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में ₹स्वस्थ लिवर, स्वस्थ जीवन₹ विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। PFWS की अध्यक्ष ऋतु अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, PFWS के पदाधिकारी, टीम लीडर्स और पुलिस परिवारों के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस जागरूकता सत्र में प्रसिद्ध लिवर विशेषज्ञ डॉ. शिव कुमार सरीन मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लिवर के स्वास्थ्य और उसके शरीर पर प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिवर फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के अनियमित और तनावपूर्ण जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और जीवनशैली में सुधार को लिवर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक बताया।

कार्यक्रम में 430 से अधिक पुलिस परिवारों के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जबकि PFWS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सैकड़ों पुलिस अधिकारी और उनके परिवार इस सत्र से जुड़े। प्रतिभागियों ने डॉ. सरीन से सीधे सवाल पूछे और लिवर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस जागरूकता अभियान को पुलिस परिवारों के बीच बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और सभी ने PFWS द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की इस पहल की सराहना की। इस सफल आयोजन ने पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वस्थ लिवर और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग की सख्त कार्रवाई, करोड़ों की हानि रोकी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग ने वर्ष 2024-25 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। विभाग की सक्रिय निगरानी और जांच से अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपये की हानि से बचाया गया।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग ने 550 से अधिक निवारक जांच कीं, जिससे रेलवे प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को सुधारा गया। इन प्रयासों से रेलवे को लगभग ₹4.46 करोड़ के संभावित नुकसान से बचाया गया। सतर्कता विभाग की प्रमुख कार्रवाइयाँः शिकायतों का त्वरित निपटानः विभाग ने 1012 शिकायतों का समाधान किया, जिसमें सीवीसी द्वारा संदर्भित 100 से अधिक शिकायतें और एक महत्वपूर्ण लोकपाल शिकायत शामिल थी। व्यवस्था में सुधारः पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए 43 अहम सिफारिशें की गईं, जिससे रेलवे पास वितरण, खानपान सेवाओं और पीआरएस काउंटरों की व्यवस्था में सुधार हुआ। टिकट घोटाले का पर्दाफाशः ट्रैवल एजेंटों और आरक्षण कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहे जाली तत्काल टिकट रैकेट का खुलासा किया गया। पुलवामा और कुपवाड़ा में जांच से नकली स्टेशनरी और ऑनलाइन ठगी के मामलों का भंडाफोड़ हुआ।

अवैध व्यापार पर सख्त कार्रवाईः नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2.32 करोड़ रुपये मूल्य की 1810 किलोग्राम अवैध रूप से आयातित सिगरेट जब्त की गई। अज्जा स्टेशन के माल गोदाम पर माल की गलत घोषणा के लिए ₹7.33 लाख का जुर्माना लगाया गया।

वित्तीय अनियमितताओं पर शिकंजाः फाजिल्का बुकिंग कार्यालय में हेराफेरी पकड़कर ₹42 लाख की वसूली की गई, वहीं ₹2.45 करोड़ की बकाया स्टाफ लागत भी सफलतापूर्वक वसूल की गई। रिश्वतखोरी पर कार्रवाईः बडगाम डीईएमयू शेड में एक डिकोय चेक के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी को ₹29,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। घटिया सामग्री पर रोकः जांच के बाद ₹2.85 करोड़ की खराब गुणवत्ता वाली लिनन सामग्री को इस्तेमाल से रोका गया। महाप्रबंधक वर्मा ने कहा कि उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है। रेलवे में नैतिक शासन, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को बरकरार रखने के लिए विभाग की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र समाप्त

कैग रिपोर्ट पर भाजपा विधायकों ने आप सरकार को घेरा, कई मामलों में आरोप

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने पूर्व आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वायु प्रदूषण मापने के लिए जितने भी उपकरण इस्तेमाल किए सभी नकली थे। प्रदूषण मापने का कोई भी विश्वसनीय पैमाना इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली में बसों के अभाव में नकली फिटनेस सर्टिफिकेट देकर बसें चलाई गईं। दिल्ली की सीमाओं पर आईएसबीटी बनने थे, जो नहीं बने। नई बसें खरीदने के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार किया गया। ईवी पॉलिसी को पिछली सरकार ने नकार दिया। वायु गुणवत्ता के नाम पर दिल्ली वासियों को गुमराह किया। वहीं, विधायक अनिल महावर ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए प्रदूषण के कारण दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। पूर्व आप सरकार ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद कनाट प्लेस में 23 करोड़ रुपये लगाकर स्मॉग टावर बनाया जो काम ही नहीं कर रहा।

दिल्ली में जब भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता था तो ये पंजाब का नाम लेकर चिल्लाते थे, लेकिन पंजाब में आप सरकार बनने पर पलट गए और पराली जलाने का इल्जाम हरियाणा पर मढ़ने लगे। दिल्ली में पराली गलाने के लिए 40 लाख रुपये खर्च कर दवा बनाई और 15 करोड़ रुपये इसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए। इधर, तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा केजरीवाल ने लोगों की जान दांव पर लगा दी। वे हमेशा यही कहते रहे कि धुंआ पंजाब से आता है, लेकिन दो साल से एक बार नहीं कहा कि धुंआ कहां से आ रहा है। धुएं की तलवार हरियाणा की ओर मोड़ दी। ये बड़ी शर्म की बात है कि पिछली सरकार के दौरान 11 साल में एक बार भी कैग रिपोर्ट सदन में नहीं आई, लेकिन काले कारनामे बाहर आ रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वायु प्रदूषण के मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर पूर्व आप सरकार पर निशाना साधा। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वाहन प्रदूषण की रोकथाम और शमन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आप सरकार के पास वायु गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर करने में असफल रही और डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाने के बावजूद उन्हें सड़कों पर नहीं उतारा गया। बजट प्रावधान होने के बावजूद मोनोरेल, लाइट रेल ट्रांजिट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बस जैसी वैकल्पिक परिवहन व्यवस्थाओं पर कोई काम नहीं किया गया। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थीं। प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे हजारों वाहनों को बिना उचित जांच के प्रमाणपत्र मिलते रहे। वर्ष 2018-19 में 64 प्रतिशत वाहनों को फिटनेस करानी थी, लेकिन अधिकांश ने फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लिया। ऑड-ईवन योजना, ट्रकों पर प्रतिबंध और ई-वाहनों को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उन्होंने लोक लेखा समिति को कैग रिपोर्ट की गहन जांच करने और अधिकारियों व नेताओं की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर अपने एक्शन टेकन नोट पेश करनी होगी।

बजट सत्र का समापन, बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बजट सत्र के समापन की घोषणा करते हुए बताया कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सूचना देंगे। बजट सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की छह रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत हुईं। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस भी हुई। दिल्ली के विकास, बजट आवंटन और विभिन्न योजनाओं को लेकर सदन में चर्चा हुई।

वर्ष 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 11,000 बसें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में दिल्ली में 6,484 बसें संचालित हो रही हैं, जबकि जरूरत 11,000 बसों की है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रूट रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि बस सेवा पूरे शहर में प्रभावी रूप से उपलब्ध हो सके। ई-बसों की संख्या बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों और डिपो का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। इस साल 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे, ताकि हरित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 1000 वाटर स्प्रिंक्लिंग मशीनें पूरे साल के लिए तैनात की जाएंगी, ताकि सड़कों पर धूल को नियंत्रित किया जा सके। राजधानी में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए छह नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदूषण स्तर की सही जानकारी मिलेगी और उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। सरकार ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए नया इको पार्क स्थापित करेगी। ट्रैफिक निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 नए कैमरे प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर लगेंगे, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करेंगे। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो वायु गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर संसाधनों के दुरुपयोग और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नीतियों और निगरानी व्यवस्था को कमजोर कर दिया, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होती चली गई। राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे और पांचवें चरण के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है, जिसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुगम बनाया जाएगा और लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे। दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की सभी योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाया जा सके।

विस के बजट सत्र में सीएजी की छह रिपोर्ट और वार्षिक बजट पेश हुआ : गप्ता

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आठवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सीएजी की छह रिपोर्ट और वार्षिक बजट पेश हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा का दूसरा सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ और 2 अप्रैल को सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के समापन के बाद गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कुल सात बैठके हुईं। इन सात बैठकों के दौरान सदन की कार्यवाही 27 घंटे 56 मिनट तक चली। इस दौरान वार्षिक बजट पेश किया गया और पास किया गया, सीएजी की छह रिपोर्ट पेश की गई और कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाए गए। लंबित कार्य निपटाने के लिए सदन की बैठकें दो दिन अर्थात 01 और 02 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 25 मार्च 2025 को वार्षिक बजट पेश किया। एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वह दिल्ली सरकार की सराहना करता हैं। इस बजट का उद्देश्य निकट भविष्य में दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना है। 26 और 27 मार्च 2025 को बजट पर सात घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 36 सदस्यों ने बजट पर चर्चा में भाग लिया, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। यह बजट पर चर्चा के लिए समर्पित सबसे लंबी अवधि थी तथा इसमें अधिकतम सदस्यों ने भाग लिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन दिल्ली सरकार के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वित्त खाते और विनियोग खाते तथा दिल्ली परिवहन निगम और वाहन प्रदूषण पर मुख्यमंत्री ने सीएजी की छह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की। 26 सदस्यों ने इन रिपोर्टों पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा पांच घंटे 32 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्षी सदस्यों ने इन चर्चाओं में भाग नहीं लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने इन रिपोर्टों पर अपने विचार प्रकट करने का एक अच्छा मौका खो दिया, जिन रिपोर्टों को उन्होंने कई वर्षों तक दबा कर रखा था। लोक लेखा समिति (पीएसी) और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सीओजीयू) का गठन किया जा चुका है और उन्हें उम्मीद है कि समितियां रिपोटों की गहन जांच करने के बाद तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन ने एक अप्रैल को दिल्ली के कुछ हिस्सों में कथित रूप से लगातार बिजली कटौती के संबंध में ध्यानाकर्षण के नोटिस पर विचार किया गया। विपक्ष के सदस्य कुलदीप कुमार ने इस संबंध में नोटिस दिया था लेकिन जब इस विषय पर सदन में विचार किया गया, उस समय कुलदीप कुमार सदन में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा विपक्ष के अन्य सदस्य भी सदन से नदारद थे। इसके बावजूद सदन में ध्यानाकर्षण को विचार के लिए लिया। कुल आठ सदस्यों ने 58 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए और मंत्री आशीष सूद ने अपना विस्तृत वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण का नोटिस देने के बाद विचार के समय विधानसभा परिसर में होने के बाद भी कुलदीप कुमार सदन में मौजूद नहीं हुए। यह एक गंभीर मामला है और इसका जवाब आने वाले सत्र में लिया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा पर दलीलें सुनीं। अदालत ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा कि बाल यौन शोषण के व्यापक और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह पीड़ित के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उसे जीवन भर परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चे को बहुत अधिक आघात का सामना करना पड़ता है। अदालत ने अपने फैसले में 2017 में हुए इस अपराध की गंभीरता और व्यक्ति द्वारा अपराध के दौरान पीड़िता को चोट पहुंचाए जाने की बात पर गौर किया। अदालत ने कहा कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

दिल्ली पुलिस के नेहरू प्लेस स्थित मालखाने में आग लगने से 100 से अधिक वाहन खाक

नई दिल्ली। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित पुलिस मालखाने में बृहस्पतिवार दोपहर आग लगने से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जब्त किए गए 100 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने के संबंध में अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर फोन आया। उन्होंने कहा कि शुरू में हमने दमकल की छह गाड़ियां मौके पर भेजी थीं और बताया गया है कि कुछ संपत्तियां भी जल गई हैं। अधिकारी ने बताया कि आग में 100 से अधिक वाहन जल गए। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। डीएफएस के अधिकारी ने कहा कि आग को पूरी तरह से बुझाने में तीन घंटे से अधिक का समय लगा और मामले की जांच के लिए तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूत्रों ने बताया कि यह मालखाना दिल्ली यातायात पुलिस का है और यातायात मुख्यालय के अधिकारी प्रभावित वाहनों की संख्या की जांच करने के लिए शीघ्र ही मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

इग्नू के परीक्षा केंद्रों और अध्ययन केंद्रों सुधार की मांग

नई दिल्ली। राजधानी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के बारे में भूमिहीन संघर्ष समिति के अध्यक्ष बालकराम ने इग्नू कुलपति को पत्र लिखकर केंद्रों की बिगड़ती स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने इग्नू कुलपति को लिखे पत्र में कहा है कि परीक्षा और अध्ययन केंद्र सरकारी स्कूलों के उच्च मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्यालयों में हुआ करते थे, जो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और समाज में सम्मानित थे। पहले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों में इग्नू के परीक्षा केंद्र होते थे लेकिन अब इसका स्तर गिर रहा है।

आतिशी-संजय सिंह को राहत, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को कोर्ट से झटका

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आप के दोनों नेता 'जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।' शिकायतकर्ता के अनुसार, एक प्रेसवार्ता में आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल 'भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने भी आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत की।'

दिल्ली में बिजली कटौती पर 'आप' कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में बढ़ते बिजली कटौती के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को आईटीओ, कालकाजी, आईएसबीटी और बुराड़ी समेत दिल्ली के कई इलाकों में 'आप' कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और 'भाजपा आई– बिजली गई' के पोस्टर लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' पर लिखा कि बिजली-पानी की भारी किल्लत के बाद अब अस्पतालों से दवाइयां भी गायब हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं और बिना दवाइयों के उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

आईएसबीटी पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगातार दो से तीन घंटे के पावर कट हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद बिजली संकट ने फिर से सिर उठा लिया है। कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अन्य 20 राज्यों में भी है, लेकिन वह अब तक किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब भाजपा सरकार उसे बर्बाद करने का काम कर रही है।

विधायक कुलदीप कुमार ने चिंता जताई कि अभी गर्मी की शुरुआत में ही दिल्ली के कई इलाकों में लंबे-लंबे पावर कट हो रहे हैं, तो मई-जून की भीषण गर्मियों में बिजली आपूर्ति की स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इनवर्टर और जनरेटर को भूल चुके थे, लेकिन अब भाजपा सरकार की नीतियों के कारण लोग फिर से इनवर्टर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और अब सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने साफ कहा कि दिल्ली में पावर कट की सरकार नहीं चलेगी। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले।

दिल्ली मेट्रो को चेन्नई मेट्रो के तीन कॉरिडोर संचालित और अनुरक्षित करने का अनुबंध

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के फेज-II के तीन कॉरिडोरों के संचालन और अनुरक्षण (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है। इनमें कॉरिडोर-3 (माधवरम मिल्क कॉलोनी से सिरुसेरी SIPCOT-II-इंडिगो लाइन), कॉरिडोर-4 (लाइटहाउस से पूनमल्ली बायपास - ऑरेंज लाइन) और कॉरिडोर-5 (माधवरम मिल्क कॉलोनी से शोलिंगनल्लूर- रेड लाइन) शामिल हैं।

इसके अलावा, माधवरम, पूनमल्ली और सेम्मांचेरी स्थित मेंटेनेंस डिपो का प्रबंधन भी डीएमआसी करेगा। यह अनुबंध 12 वर्षों की अवधि के लिए रहेगा, जो फेज-II के अंतिम चरण की वाणिज्यिक संचालन तिथि से प्रभावी होगा।

चेन्नई में CMRL मुख्यालय में इस अनुबंध के संबंध में औपचारिक 'किक-ऑफ मीटिंग' आयोजित की गई, जिसमें DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार, निदेशक (ऑपरेशंस एंड सर्विसेज) डॉ. अमित कुमार जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। DMRC इन तीन कॉरिडोरों के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा, जिनकी कुल लंबाई 116.1 किलोमीटर होगी और इन पर 112 स्टेशन होंगे, जिनमें छह डबल डेकर स्टेशन भी शामिल हैं। DMRC संचालन नियंत्रण केंद्र (OCC), डिपो नियंत्रण केंद्र, स्टेशनों, ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के रखरखाव और संपूर्ण मेट्रो सिस्टम के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करेगा। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के फेज-II का पहला खंड दिसंबर 2025 तक परिचालन में आ सकता है, जबकि संपूर्ण फेज-II को दिसंबर 2028 तक चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि DMRC मई 2023 से मुंबई मेट्रो की लाइन-3 का संचालन और रखरखाव भी कर रहा है। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए है और इसमें 33.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन तथा 27 स्टेशन शामिल हैं। इस लाइन के पहले चरण (आरे से BKC तक, 12.4 किलोमीटर और 10 स्टेशन) का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी पकड़ा गया

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहम्मद सदीकुर रहमान (25) के रूप में हुई है, जो इलाज के लिए भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। उन्होंने बताया, ''एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने होटल बदल-बदल कर रह रहे रहमान को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से देश में रहने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं के बाद रहमान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) निर्वासन केंद्र भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि और अधिक अवैध प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए अभियान जारी है।

संपादकीय
आदित्य वशिष्ठ

अमित शाह का बजा सियासी बिगुल

बुलडोजर से नाइंसाफी

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अन्याय केवल झुग्गियों व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है, बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। अदालत ने प्रयागराज में घरों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनहीनता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तस्वीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदनशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादास्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली 'भाषा' में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी हैं कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा। बीते साल नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कई दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से 15 दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य-सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए, लेकिन सभी कायदे-कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई।

नीतीश पिछले दो दशकों से बिहार में राजग का 'चेहरा' रहे हैं लेकिन अटकलें हैं कि जेडीयू प्रमुख के कथित खराब स्वास्थ्य को देखते हुए भाजपा इस बार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। पहले, नीतीश कई बार अचानक राजग का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि, कुमार यह दोहराते रहे हैं कि वे हमेशा के लिए राजग में वापस आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सभी दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर खास प्लानिंग पर विचार किया है। भाजपा के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर यूं ही नहीं हमलावर है। इस बार अमित शाह को लालू यादव का वो स्वरूप याद आ रहा है जिन्होंने आरक्षण के रथ पर सवार हो कर भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देकर उनके हाथों से जीत छीन ली थी। 2015 में लालू यादव को एक मुद्दा 'आरक्षण' मिला था। इस बार तो लालू यादव दो धारी तलवार भांज रहे हैं। लालू यादव वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी ठहराने लगे हैं और साथ ही 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालने को 'आरक्षण चोर' बताने लगे हैं। इधर, राजद के नेता अब केंद्रीय गृहमंत्री शाह पर पलटवार कर रहे हैं। राजद की सांसद मीसा भारती ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार को तीन कारखाने दिए थे। शाह को यह पता होना चाहिए कि बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया है, तो वे लालू हैं। अगर कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो रेलवे के वही तीन कारखाने हैं जो लालू यादव की सरकार में बने।

- कुमार कृष्णन

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय बिहार दौरे के क्रम में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, वहीं विपक्ष को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा। उन्होंने राजद और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया तो परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख कुमार के आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सहयोगियों के साथ इस साल के अंत में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। नीतीश लंबे समय से बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की धुरी रहे हैं।

अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यह संकेत साफ हो गया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अस्तित्व नीतीश कुमार के बिना अधूरा है। इसीलिए बैठक में तय हुआ कि पूरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन टीम एकजुट होकर अधिक से अधिक सीटें जीतने की रणनीति पर काम करेगी। राजग का लक्ष्य इस बार 225 सीटें जीतने का है। बैठक में तय हुआ कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ और साझा चुनावी अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान भाजपा, जदयू, हम और लोजपा रामविलास सहित सभी राजग के सहयोगी दल मिलकर विपक्ष को घेरेंगे। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. इनमें से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 225 सीटें जीतने का लक्ष्यम रखा है। बिहार में सामान्य बहुमत से सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है, ऐसे में यदि बिहार में एनडीए 225 सीटें जीतने में सफल रहता है तो गठबंधन को दो तिहाई बहुमत हासिल हो जाएगा। बैठक में इस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, इसको लेकर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही तय हुआ है कि राजग आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस रहेगा। पार्टी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए शाह ने कहा कि जो भी कमी है, उसको ताकत में बदलना है। जिन बूथों पर हम हारते हैं या कम वोट आता है, उन बूथों को जीतना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में यह रणनीति सफल हुई। शाह ने ऐलान किया कि छह अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। बिहार में राजग का यही स्वरूप रहेगा। राजग बिहार में स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलराज नहीं आए, इसके लिए संकल्पित होकर बीजेपी काम करेगी. आरजेडी के शासनकाल के जंगलराज के मुद्दे को चुनाव में उठाया जाएगा।

अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने बिहार के पटना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि विपक्षी सरकारों के शासनकाल में बिहार में सहकारिता को पूरी तरह चौपट कर दिया गया था और सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गईं थीं। उन्होंने कहा कि एक जमाने में बिहार का चीनी उत्पादन देश के चीनी उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक था जो विपक्षी सरकारों के कार्यकाल में घटकर 6 प्रतिशत से भी कम रह गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक विपक्षी सरकारों ने बिहार में हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट की एक इंडस्ट्री चलाई जिसने राज्य को पूरी तरह से बरबाद कर दिया। शाह ने कहा कि बिहार में विपक्षी सरकारों के शासनकाल में जातीय नरसंहार हुए, सत्तापोषित भ्रष्टाचार हुआ और चारा घोटाले से राज्य को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हर गांव तक सड़क, बिजली और नल से जल पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाएं, राशन देकर बिहार के गरीबों के कल्याण के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बिहार को 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि मोदी सरकार के 10 साल में बिहार को 9 लाख 23 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। शाह ने कहा कि बिहार में 4 लाख करोड़ रुपये के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स और 2 हजार करोड़ रुपये के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ रुपये से बिहार में 7 बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है, 31 हजार करोड़ रुपये से 5 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइन बन रही है और देश में पहली किसान रेल भी बिहार से ही शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया और बरौनी के खाद कारखाने सहित 766 अन्य प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार की मदद से राज्य में शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का विकास का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अब यहां से जंगलराज समाप्त हो चुका है।

नीतीश पिछले दो दशकों से बिहार में राजग का 'चेहरा' रहे हैं लेकिन अटकलें हैं कि जेडीयू प्रमुख के कथित खराब स्वास्थ्य को देखते हुए भाजपा इस बार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। पहले, नीतीश कई बार अचानक राजग का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि, कुमार यह दोहराते रहे हैं कि वे हमेशा के लिए राजग में वापस आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सभी दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर खास प्लानिंग पर विचार किया है। भाजपा के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर यूं ही नहीं हमलावर है। इस बार अमित शाह को लालू यादव का वो स्वरूप याद आ रहा है जिन्होंने आरक्षण के रथ पर सवार हो कर भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देकर उनके हाथों से जीत छीन ली थी। 2015 में लालू यादव को एक मुद्दा 'आरक्षण' मिला था। इस बार तो लालू यादव दो धारी तलवार भांज रहे हैं। लालू यादव वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी ठहराने लगे हैं और साथ ही 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालने को 'आरक्षण चोर' बताने लगे हैं। इधर, राजद के नेता अब केंद्रीय गृहमंत्री शाह पर पलटवार कर रहे हैं। राजद की सांसद मीसा भारती ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार को तीन कारखाने दिए थे। शाह को यह पता होना चाहिए कि बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया है, तो वे लालू हैं। अगर कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो रेलवे के वही तीन कारखाने हैं जो लालू यादव की सरकार में बने। लालू यादव ने बिहार में छह विश्वविद्यालय देने का काम किया, उसके बाद सातवां विश्वविद्यालय यहां नहीं बना।

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पटना के बापू सभागार में दिए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए और भाजपा के नेताओं का काम योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ के नाम पर केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरना है, काम से मतलब नहीं है। ऐसी योजनाओं की एक लंबी सूची है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि दस वर्षों से केंद्र में और लगभग दो दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज भाजपा नेता विपक्षी नेताओं से कामों का हिसाब मांग रहा है। इसकी जानकारी तो उन्हें सरकारी दस्तावेजों से ही मिल जाएगी। राजद के शासनकाल से एनडीए के शासनकाल में आपराधिक घटनाओं में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले गृहमंत्री को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश कुमार पर लगाए गए भ्रष्टाचार और घोटालों की सूची भी देख लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि दरअसल बिहार की जनता उनसे जानना चाहती है कि 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने बिहार को क्या दिया?

गुजरात हादसा: कब तक जिन्दा दफन होते रहेंगे बेकसूर मजदूर

- नरेंद्र भारती

बेकसूर मजदूर कब तक जिन्दा जलते रहेंगे यह एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में मजदूरों के मरने की खबरें सुखियां बनती है मगर सरकारें मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही हैं। देश के कारखानों में मजदूर मर रहे हैं हर जगह मजदूर काल का ग्रास बन रहे है। ताजा हादसा एक अप्रैल (मंगलवार) को गुजरात के बनासकांठा जिले में एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद आग लगने से और ईमारत ढह जाने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

ऐसा ही हादसा 12 अक्टूबर 2024 को गुजरात के मेहसाणा के कड़ी कस्बे मे घटित हुआ था जहां काम करते समय 9 मजदूर जिन्दा दफन हो गए थे सभी मजदूरों के शव निकाल दिए थे दफन होने वाले मजदूर 25 से तीस साल के थे। मजदूरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा की उनकी इतनी दर्दनाक मौत होगी। देश में मजदूरों के साथ हादसे कब थमेगें यह एक यक्ष प्रशन है। हर साल दिवस मनाए जाते है मगर धरातल की सच्चाइयां बहुत ही भयानक है मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूरों के नाम पर सैकडों योजनाए चलाई जाती है मगर उन्हे उनका हक नहीं मिलता। देश में हर रोज मजदूर बेमौत मर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तरकाशी में बेकसूर मजदूरों ने 17 दिन और 16 रातें कैसे निकाली थी यह मजदूर ही जानते होंगे। खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। 17 दिन सूर्य क़े दर्शन नहीं हुए थे। मजदूरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था की जिस सुरंग का निर्माण कर रहे हैं उसमें कैद हो जाएंगे। करोड़ों देश वासिओं की दुआएं रंग लाई और मजदूरों को नया जीवन मिल गया और 12 दिन सुरंग की कैद से मुक्त हो गए थे। 12 तारीख को एक तरफ रविवार को दीपावली के दिन जहां पूरा भारतवर्ष दिवाली की खुशियां मना रहा था वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में बहुत ही भयंकर दुःखद हादसा हुआ था जब सुरंग ढहने से 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे। उत्तरकाशी के सिल्कयारा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी सुरंग में फंसे 41 मजदूर जिंदगी व मौत के बीच झूल रहे थे सरकार द्वारा मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू अभियान का 17 दिन ऑपरेशन जारी रहा था और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था।

देश प्रतिदिन समाचार पत्रों में मजदूरों के मरने की खबरें सुखियां बनती है मगर सरकारें मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही हैं। देश में मजदूरों के साथ हादसे थमने का नाम नहीं ले रहें हैं। हर साल दिवस मनाए जाते है मगर धरातल की सच्चाइयां बहुत ही भयानक है मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूरों के साथ होने वाले यह हादसे बहुत ही त्रासदी है। कहीं उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं। हादसों की बजह से बच्चे अनाथ हो रहे है। मगर केंद्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है। देश में हर वर्ष लाखों मजदूर दबकर मारे जा रहे हैं उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं।

मगर केंद्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है। देश के कारखानों में मजदूर मर रहे हैं, इमारतों के नीचे दबकर मजदूर काल का ग्रास बन रहे है। हादसों को देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं देश के राज्यों में चल रहे ईटों के भट्ठों में मजदूर मारे जा रहे हैं। मजदूरों के पसीने से ही ईटें पकती हैं मगर भट्ठा मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं मजदूर खून-पसीना बहाकर काम करते है। मगर बदले में मेहनताना नाममात्र दिया जाता है। मालिक मजदूरों के सिर पर करोड़ों रुपया कमा रहे है। आकड़ों के मुताबिक बीते सालों में देश में हजारों मजदूर मारे जा चुके है। हादसों ने सवाल खड़े कर दिये हैं कि बार-बार हो रहे इन हादसों के कारण क्या है इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बीती घटनाओं से न तो सरकार ने सबक सिखा और न ही लोगों ने सीखा। हांलाकि इसयह कोई पहला हादसा नहीं है पिछले कई सालों से ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। बीते वर्ष में रायबरेली के उंचाहार में एटीपीसी संयत्र का बायलर फटने से 30 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी तथा 100 के लगभग घायल हो गए थे। 500 मैगावाट इकाई के बायलर में यह हादसा हुआ था उस समय 200 कामगार मौजूद थे सरकारों ने मृतकों को मुआवजे की घोषणा करती है मगर मुआवजा इसका हल नहीं है। एक ऐसा ही हादसा जयपुर के पास खातोलाई गांव में घटित हुआ था जहां टासफारमर फटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इन हादसों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा पर प्रशनचिन्ह लगा दिया है इन हादसों पर संज्ञान लेना होगा तथा मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होगें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके।

गत वर्ष जम्मू के उधमपूर से 80 किलोमीटर दूर रामबन जिले के चंद्रकोट में जम्मू-कश्मीर हाईवे पर टनल कर्मचारियों की बैरक में आग लगने से दस श्रमिक जिंदा जल गए थे। गत वर्ष एक निर्माणाधिन प्रोजेक्ट की दीवार गिरने से चार मजदूर बेमौत मारे गए। यहां पर 11 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई सात मजदूर तो भागकर बच गए मगर बेचारे चार मजदूर जिन्दा दफन हो गए थे। इन मजदूरों पर 42 मीटर लंबी दीवार गिर गई यह बहुत ही दुखद हादसा था। गोवा के कनाकोना शहर में फिर एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। जब यह इमारत ढही उस समय 40 लोग काम कर रहे थे इस घटना ने सवाल खड़े कर दिये हैं कि बार-बार हो रहे इन हादसों के कारण क्या है इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बीती घटनाओं से न तो सरकार ने सबक सिखा और न ही लोगों ने सीखा। हालांकि यह कोई पहला हादसा नहीं है पिछले कई सालों से ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं गत वर्ष महाराष्ट्र में एक इमारत के गिरने से 75 मजदूरों की असमय मौत गई थी और 60 मजदूर घायल हो गए थे आखिर कब तक मजदूर इमारतों में जमीदोज होते रहेंगे। कुछ दिन पहले निर्माणाधीन यह इमारत ताश के पतों की तरह ढह गई यहां ज्यादातर मजदूर ही रह रहे थे। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसने एक साथ इतने लोगों को लील लिया।

प्रशासन मुआवजे का मरहम लगाता है मगर जो बेमौत मारे गये क्या वे लौट आएगें यह एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। सरकार ऐसी घटनाओं के बाद मुआवजों की घोषणा करने तथा जांच के आदेश देने में देरी नहीं करती लेकिन यदि पहले ही इन लोगों पर करवाई कर ली जाए तो ऐसे हादसे रुक सकते है मगर सरकारों की तन्द्रा तो हादसे के बाद ही टूटती है। आखिर कितने हादसों के बाद प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभायेगा इस प्रश्न का जबाब सरकार को देना होगा। इमारतों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को सजा ए मौत देनी चाहिए जो इन हादसों के लिये प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेवार है। जो चंद चादी के सिक्कों की चाहत के लिए मजदूरों की जिन्दगियां ले रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।

हनुमान जी को अर्पित करें कुछ खास, घर से दूर होगा अन्न और धन का अभाव

धर्मकर्म

हनुमान जी को तुलसी प्रिय होने की एक प्रमुख वजह है उनकी भक्ति और तपस्या की विशिष्टता। तुलसी का पौधा पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो समृद्धि और भाग्य की देवी हैं। हनुमान जी की भक्ति और साधना में तुलसी का महत्व इसलिए है क्योंकि तुलसी का पौधा शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। हनुमान जी की पूजा में तुलसी की पत्तियां अर्पित करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। यह माना जाता है कि तुलसी की पत्तियां भगवान श्रीराम के साथ हनुमान जी के गहरे संबंध को दर्शाती हैं। तुलसी की पूजा से मन की शांति और भक्ति में वृद्धि होती है, जो हनुमान जी के भव्य व्यक्तित्व से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त तुलसी की औषधीय गुण भी हनुमान जी की प्रियता को बल देते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वास्थ्य और शक्ति के प्रतीक भी हैं। हनुमंत उपासना अगर भक्ति, श्रद्धा, समर्पण एवं संलग्नता से की जाए तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार के अनिष्ट ग्रहों के प्रकोप से कोई ग्रस्त हो तो हनुमान जी की शरण में आने से सभी ग्रहों का क्रूर प्रभाव स्वतः ही दूर हो जाता है। जहां हनुमान उपासना होती है वहां दुर्भाग्य, दारिद्रय, भूत-प्रेत का प्रकोप, असाध्य रोग और शारीरिक कष्ट कभी समावेश नहीं कर पाते। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। तुलसी भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को अर्पित की जाती है। तुलसी के अभाव में उनको कोई भी भोग अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी भगवान राम को बहुत प्रिय है, जो चीज श्रीराम को प्रिय है वो हनुमान जी को तो प्रिय होगी। अगर प्रतिदिन हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाएं जाएं तो घर में कभी भी अन्न और धन का अभाव नहीं रहता। हनुमान जी को गुड़-चने, मधु-मुनक्का, बेसन के मोदक, केले का भोग बहुत प्रिय है। भोग देते समय उसमें तुलसी पत्र अवश्य दें। याद रखें जब भी हनुमान जी को कोई भी भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी अवश्य डालें तभी वह तृप्त हो पाएंगे।

आज का इतिहास

1768 - फिलिप एस्ले ने माडर्न सर्कस का पहला शो पेश किया।
1769 - हैदर अली ने पहले एंग्लोः मैसूर युद्ध में शांति की शर्तें तय कीं।
1818 - अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका के झंडे को मंजूरी दी।
1905 - भारत की कांगड़ा घाटी में भूकंप से 20,000 लोगों की मौत।
1910 - अरबिंदो पुडुचेरी पहुंचे जो बाद में उनके ध्यान और अध्यात्म का केंद्र बना।
1944 - द्वितीय विश्व युद्ध में एंग्लो अमेरिकी सेना की बुखारेस्ट में तेल शोधन संयंत्रों पर पहली बमबारी। तीन हजार नागरिकों की मौत।
1968 - नासा ने अपोलो-6 का प्रक्षेपण किया।
1975 - बिल गेट्स और पॉल एलेन के बीच भागीदारी से न्यू मैक्सिको के अल्बकर्क में माइक्रोसाफ्ट की स्थापना।
1979 - पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की सजा।
1983 - अंतरिक्ष शटल चैलेंजर ने अपनी पहली उड़ान भरी।
2020 - दुनियाभर में कोराना वायरस से 59 हजार से अधिक लोगों की मौत।

जन्म

1889 - हिन्दी के कवि, लेखक, पत्रकार माखन लाल चतुर्वेदी।
1915 - भारत के महान क्रांतिकारी असित भट्टाचार्य।
1933 - पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बापू नादकर्णी।

निधन

1968 - मार्टिन लूथर किंग। टेनेसी के मेमफिस में एक मोटेल में हत्या।
1987 - सुप्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय।

जल और ऊर्जा: मितव्ययिता के साथ विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी!

- सुनील कुमार महला

वर्तमान में अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी से ठीक-ठाक गर्मी पड़ने लगी है। अभी से ही उत्तर भारत गर्मी का सामना करने लगा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में इस संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का यह अनुमान है कि इस बार अप्रैल में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। गौरतलब है कि आईएमडी द्वारा कई इलाकों में 'लू' (गर्म हवाएं) का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है। कहना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने आने वाले महीनों में सामान्य से अधिक गर्मी और हीटवेव को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, वह जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट को इंगित करता है।

आईएमडी के मुताबिक देश में अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में 'लू' चल सकती है। आशंका जताई गई है कि पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। वास्तव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप दिखेगा। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे धरती पर गर्म लहरों की तीव्रता बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य, जीवों के स्वास्थ्य, वनस्पतियों और देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है।

सच तो यह है कि अत्यधिक गर्मी उद्योगों और व्यवसायों के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है। कहना गलत नहीं होगा कि गर्मी बढ़ने से उत्पादकता में अभूतपूर्व कमी आती है। उच्च तापमान के संपर्क में आने वाले कर्मचारी गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे कार्य कुशलता कम हो जाती है और उत्पादकता प्रभावित होती है। अत्यधिक गर्मी आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे कि परिवहन व रसद में देरी) को बाधित कर सकती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, शीतलन उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की खपत में जबरदस्त वृद्धि होती है। यह बढ़ी हुई मांग बिजली ग्रिड पर दबाव डालती है, जिससे संभावित रूप से बिजली की कटौती होती है और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर व्यवसायों पर असर पड़ता है और ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। कहना चाहूंगा कि अत्यधिक गर्मी से कई तरह से वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिसमें कृषि में फसल की विफलता, पर्यटन पर निर्भर व्यवसायों के लिए पैदल यातायात में कमी, तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के रख-रखाव की लागत में वृद्धि शामिल है। बहरहाल, मौसम वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से यह चेतावनी जारी कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान) में बढ़ोत्तरी की वजह से दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। गौरतलब है कि पिछले ही वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में पहली हीटवेव ओडिशा में अप्रैल की शुरुआत में महसूस की गई थी, जबकि इस वर्ष कोंकण व तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फरवरी का अंत आते-आते ही होटवेव जैसी स्थितियां पैदा होने से मौसम को लेकर पहले ही अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं।

यह बात ठीक है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को एकदम से रातों-रात नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम गर्मी रोकने वाली गैसों और कालाशे कार्बन के मानव उत्सर्जन को कम करके इसकी दर को धीमा कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा को काफी हद तक सीमित कर सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्याओं को समायोजित करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मसलन, रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण), परिवहन के तरीकों को बदलकर, भोजन की बर्बादी को रोककर, अपनी ऊर्जा खपत का उचित प्रबंधन करके तथा दूसरों को पर्यावरण के प्रति शिक्षित और जागरूक करके काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। आज विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है और इसके लिए मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना जिम्मेदार ठहराते जा सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये गतिविधियां ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ती हैं, और हमारे नीले ग्रह के नाजुक जलवायु संतुलन को बिगाड़ती हैं।

संक्षेप में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि से है और यही तापमान वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। सच तो यह है कि तापमान में निरंतर वृद्धि दुनिया भर में व्यवधानों को बढ़ावा देती है। मसलन, अधिक चरम गर्मी पिघलती बर्फ की टोपियों से लेकर बारिश के बदलते पैटर्न तक, कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ता है। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलने लगतीं हैं। उच्च तापमान से तूफान, वन्य आग, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैव-विविधता की हानि होती है। सच तो यह है कि आज कई प्रजातियां बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप विलुप्ति हो रही है। तापमान बढ़ोत्तरी से महासागरों का अम्लीकरण होता है। इससे अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में घुल जाती है, जिससे पीएच स्तर में परिवर्तन होता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। धरती का तापमान बढ़ता है तो भोजन एवं पानी की कमी हो जाती है। सच तो यह है कि सूखे और अनियमित मौसम से फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। वायु प्रदूषण और अत्यधिक गर्मी श्वसन संबंधी बीमारियों और हीटस्ट्रोक में योगदान देती है। संक्षेप में कहें तो इससे स्वास्थ्य पर संकट बढ़ते हैं।

बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि यदि हमने समय रहते अपने कार्बन उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैसों) को नियंत्रित नहीं किया और पर्यावरण संरक्षण को उचित प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले वर्षों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आज वनों की कटाई, चरागाहों में लगातार कमी और अनियंत्रित औधोगिकीकरण और शहरीकरण ने मौसम चक्र को असंतुलित किया है, जिससे मौसम संबंधी असामान्य घटनाएं भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो वर्ष 2015 में पेरिस में हुआ था लेकिन अमेरिका ने पेरिस समझौते से दूरी बनाकर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

वक्फ (संशोधन) विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा: विपक्ष

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से देश में धर्म निरपेक्ष माहौल बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश में गरीबी से लेकर और भी कई समस्याएं हैं जिनके खिलाफ जंग जरूरी है और यह विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को संविधान विरोधी बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।

उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के माध्यम से बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान पर आघात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि यह कानून मुसलमानों के भले के लिए है जबकि संसद के दोनों सदनों में सत्ताधारी दल का केवल एक मुसलमान सदस्य है और मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। सिंह ने इस विधेयक को 'धार्मिक संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश' करार देते हुए कहा कि धीरे धीरे दूसरे धर्मों की संपत्ति भी इसी तरह कब्जा की जाएगी।

उन्होंने सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2013 में भाजपा के समर्थन से पारित हुए विधेयक में भी वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह देने का प्रावधान था। सिंह ने कहा कि सरकार को लोकसभा चुनाव में केवल 36 फीसदी वोट मिले जिससे साफ है कि देश की 64 फीसदी आबादी उसके खिलाफ है। क्या गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में गैर सिखों को सदस्य बनाया जा सकता है? क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सदस्य बनाया जा सकता है? फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों रखा जाना चाहिए? उन्होंने सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नये विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही जमीन वक्फ़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कैसे पता लगाएगी कि जमीन वक्फ़ करने का इच्छुक व्यक्ति पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है? क्या उसके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे? क्या यह पता करेंगे कि वह नमाज पढ़ता है या नहीं?

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि देश के बंटवारे के बाद समुदायों के बीच विश्वास की कमी थी जिसे संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के जरिये दूर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को आज का माहौल देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या उसके पास बहुत बड़ा बहुमत है? 'हमारी आदत बन गई है समुदायों को हाशिये पर छोड़ने की।' झा ने कहा कि इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की और मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। 'सरकार यह आदत मत बदलवाए।'

उन्होंने कहा कि पहले देश का माहौल पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बनाएं तब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को रखने की बात की जाए अन्यथा 'एक कौम के साथ प्रयोग न करें।' उन्होंने कहा कि गरीबी और अन्य समस्याओं के खिलाफ जंग छेड़ना चाहिए, न कि ऐसे विधेयक पर जोर देना चाहिए। उन्होंने विधेयक पर पुनः विचारविमर्श करने का सुझाव दिया।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वेंकट सुब्बा रेड्डी ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि यह मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल मुसलमानों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ बल्कि समानता के अधिकार के खिलाफ भी है और इसे मुसलमानों की जमात कभी मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मसौदा कानून को नहीं मानेंगे।

> "बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि पहले अगर किसी के पास अधिक जमीन होती थी तो वह उसे वक्फ को विकास कार्य के लिए देता था ताकि वहां स्कूल या अस्पताल या ऐसा कोई उपयोगी संस्थान बन जाए। उन्होंने कहा कि बाद में हालात बदले, लेकिन ऐसे हालात नहीं आए कि यह विधेयक लाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करती है लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि मुसलमान उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के मन में छिपे डर को दूर करे, क्योंकि वह सबकी सरकार है। उन्होंने मांग की कि नमाज का समय हो जाने पर कहीं भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा हो तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओडिशा की पहचान भगवान जगन्नाथ के नाम से है और पुरी में भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर से रथ यात्रा निकलती है और सालबेग की मजार के पास रुकती है। 'भगवान अपने भक्त सालबेग से मिलते हैं और वहां भोग चढ़ाने के बाद यात्रा आगे बढ़ती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है जो सद्भाव की एक मिसाल देती है।' उन्होंने मांग की कि सरकार यह आश्वासन दे कि वक्फ की जमीन किसी दूसरे लोगों को नहीं दी जाएगी।

वक्फ विधेयक असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफः मोहम्मद नदीमुल हक

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि यह विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ ही राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा है और यह मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। उन्होंने इस विधेयक को गैर-जरूरी कदम बताया और कहा कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। हक ने कहा कि संविधान कोई किताब नहीं बल्कि देश को रास्ता दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संघवाद की भावना के खिलाफ भी है और इसमें सुधारों के नाम पर परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारी छीने जा रहे हैं। तृणमूल सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि वक्फ मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और सरकारी अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने इसे भेदभावकारी बताते हुए कहा कि कम से कम पांच साल तक मुस्लिम धर्म का अनुसरण करने वाले ही वक्फ के कामकाज से जुड़ सकेंगे। उन्होंने सवाल किया कि यह कौन तय करेगा कि अमुक व्यक्ति पांच साल से मुस्लिम धर्म का भलीभांति अनुसरण कर रहा है या नहीं। हक ने कहा कि इस विधेयक में संपत्ति के दस्तावेजों पर भी जोर दिया गया है लेकिन कई संपत्ति पीढ़ियों से हैं और मौखिक आधार पर दिए गए थे, वैसे मामलों में दस्तावेज कैसे उपलब्ध होंगे।

आरोप साबित करें या इस्तीफा दें, आरोप सही हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा: खरगे

अनुराग ठाकुर की कांग्रेस अध्यक्ष पर टिप्पणी के विरोध में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉक आउट किया

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और सदन से वॉक आउट किया।

गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति के समक्ष अनुराग ठाकुर के आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरे 60 साल के संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन में इस तरह के झूठे और आधारहीन आरोप जो लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने लगाए, वह अवमाननापूर्ण है। जब मेरे सहयोगियों ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्हें अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन नुकसान तो हो चुका है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया ने उस बेबुनियाद आरोपों वाले बयान को प्रसारित कर दिया। खरगे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष के नाते मैं अनुराग ठाकुर के आरोपों की निंदा करता हूं। अगर अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करने में विफल साबित होते हैं तो उन्हें संसद में बने रहने का अधिकार नहीं है। तब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने आरोपों को साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं उससे जुड़े दस्तावेज यहां टेबल कर रहा हूं।

खरगे ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा यहां सदन में बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कभी कोई विधानसभा सदन में इस तरह नहीं बोला। अगर कभी कोई बोला तो सीएम ने बगल में आकर माफी मांगी। मैं कभी झूठ नहीं बोला और न ही कोई गलत काम किया। इस पर भाजपा के सदस्यों ने प्रतिवाद किया तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से शोरशराबा और हंगामा शुरू हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कुछ बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन हंगामे के कारण वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके। हंगामे के बीच खरगे ने सभापति से सरंक्षण की अपील की कि अनुराग ठाकुर के आरोपों को लेकर यहां जो कुछ हुआ, नेता सदन को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

इस बीच सभापति ने सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस व उनके अन्य सहयोगी विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉक आउट कर गये।

संसदीय संस्था के सम्मान में कार्यवाही से कुछ हटाया जाता है, तो इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिएः सभापति

सभापति ने कहा यदि हम इस मुद्दे की गंभीरता से जांच करें, तो यह कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। एक मुद्दा यह है कि एक संसद सदस्य सदन का सदस्य होने के महान विशेषाधिकार का उपयोग करता है, जो संवैधानिक संरक्षण है क्योंकि सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। जब कोई सदस्य सदन में बोलता है, तो उसे छूट दी जाती है। मैंने कई मौकों पर यह कहा है कि हम दशकों और आधी सदी से अर्जित प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी सप्ताह मैंने खरगे जी की तरह अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की थी, जब इस सदन के एक सदस्य ने टिप्पणी की थी, लेकिन उस पर ध्यान दिया गया। हालांकि सदस्य ने हटाए गए तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने इस सदन को संकेत दिया था कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, विस्फोटक सोशल मीडिया में, कही गई कोई भी बात माइक्रोसेकंड में ध्यान आकर्षित कर लेती है। इसलिए, अध्यक्ष द्वारा हटाए गए तथ्य शायद ही कोई उपाय हों। हमने खरगे की प्रतिष्ठा जैसी स्थितियों का सामना किया, और फिर राणा सांगा एक मुद्दा बन गए, लेकिन सदस्य ने अपना रुख अपनाया कि जब तक वे जीवित हैं, वे इसे दोहराते रहेंगे। मैंने तब एक बात कही थी- अगर इस संसदीय संस्था के सम्मान में कुछ हटाया जाता है, तो किसी भी सदस्य को इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सदस्य ने अपनी बात जारी रखी। वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर, अगली बारी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति की हो सकती हैः उद्धव ठाकरे

मुंबई। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और अगली बारी मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की जमीन की हो सकती है।

उद्धव ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक पर भाजपा के कपटपूर्ण रुख और 'वक्फ की जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल' का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और विधेयक का समर्थन करने वाले उसके सहयोगी दलों द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्रति दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक (मुहम्मद अली) जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। उद्धव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवसेना (उबाठा) पर वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन न करके हिंदुत्व और पार्टी संस्थापक बाल उद्धव के आदर्शों को त्यागने का आरोप लगाया है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी नजर वक्फ की जमीन पर है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट, गिरजाघरों, गुरुद्वारों के पास भी जमीन है। आपकी नजर हम (हिंदू मंदिरों की जमीन) पर भी हो सकती है। यह विधेयक सिर्फ जमीन के लिए लाया गया है। हमने इस कपट का विरोध किया है। उन्होंने सवाल किया कि

अगर वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए है, तो इसे लाकर किसने हिंदुत्व को त्यागा है। वक्फ विधेयक का हिंदुत्व से क्या संबंध है? इससे हिंदुओं को क्या लाभ होगा? हालांकि, उद्धव ने स्वीकार किया कि विधेयक में कुछ अच्छी बातें हैं और कहा कि उनकी पार्टी नकारात्मक राजनीति का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए।

उद्धव ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है और चीजें सामान्य हैं, फिर भी वह हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति फूट डालना, लड़ाई करवाना और राज करना है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को अमेरिकी शुल्क के आसन्न खतरे और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों को अन्य सभी कार्यों को स्थगित कर भारत पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव पर चर्चा करनी चाहिए थी।

कठुआ के जंगलों में छिपे 3 घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बहुस्तरीय अभियान लगातार 12वें दिन भी जारी

जम्मू। तीन मुठभेड़ों से बचकर भागे और कठुआ के एक जंगली इलाके में छिपे तीन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बहुस्तरीय अभियान लगातार 12वें दिन भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकवादियों के समर्थकों पर नकेल कस रही हैं और घात लगाकर हमला कर रही हैं। बहुस्तरीय घेराबंदी को मजबूत करने और क्षेत्र में 6-7 किलोमीटर के दायरे में घात लगाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए यह अभियान चल रहा है। हेलीकॉप्टर, यूएवी और खोजी कुत्तों के इस्तेमाल सहित हवाई निगरानी के साथ तलाशी अभियान को तेज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सेना, एनएसजी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीमें क्षेत्र को कवर करने के लिए सभी इलाकों की तलाशी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवादी ऊपरी इलाकों की ओर न भाग जाएं, बीहड़ इलाकों और घने जंगलों में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। सैनिकों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़े क्षेत्र में कई घात लगाए हैं। उन्होंने ऑपरेशन के क्षेत्र का विस्तार करके बिलावर, भड्डू, घट्टी और कोग-मंडली को शामिल किया है।

शीर्ष सैन्य नेतृत्व वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाएः राजनाथ सिंह

साइबर, सूचना, संचार, व्यापार और वित्त सभी भविष्य के संघर्षों का अभिन्न अंग बनेंगे

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सेना के कमांडरों से वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए योजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वैश्विक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और ऐसी घटनाएं चाहे हमारे पड़ोस में हों या दूर के देशों में, सभी को प्रभावित करेंगी। उन्होंने कहा कि 'हाइब्रिड युद्ध' भविष्य के पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे। साइबर, सूचना, संचार, व्यापार और वित्त सभी भविष्य के संघर्षों का अभिन्न अंग बनेंगे। इसलिए सशस्त्र बलों को अपनी योजना और रणनीति बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

रक्षा मंत्री नई दिल्ली में चल रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में तीसरे दिन के सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने वर्तमान भू-रणनीतिक अनिश्चितताओं और जटिल विश्व स्थिति पर जोर दिया, जो वैश्विक स्तर पर सभी को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान गतिशील भू-रणनीतिक परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के साथ चल रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों चुनौतियों का समाधान करते हुए योजना तैयार करनी चाहिए। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में आधुनिक तकनीक को शामिल करने वाली सैन्य खुफिया के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीमा की मौजूदा स्थिति पर तैनात सशस्त्र बलों की दृढ़ता और सतर्कता के लिए सराहना की तथा कहा कि ऐसा ही जारी रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने बीआरओ के प्रयासों को सराहा, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सड़क संचार में भारी सुधार हुआ है। सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के अलावा नागरिक प्रशासन को हर समय सहायता प्रदान करने में सेना की सराहनीय भूमिका पर प्रकाश डाला।

रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना सुरक्षा, एचएडीआर, चिकित्सा सहायता से लेकर देश में स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने तक हर क्षेत्र में मौजूद है। उन्होंने सेना कमांडरों के सम्मेलन में राष्ट्र के 'रक्षा और सुरक्षा' दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक ले जाने के लिए सेना नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के प्रति भारतीय सेना की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि विरोधी की ओर से छद्म युद्ध जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीएपीएफ, पुलिस बलों और सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में समन्वित अभियान क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य बलों की उच्चस्तरीय परिचालन तैयारियों और क्षमताओं का अनुभव वे हमेशा अग्रिम क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान करते रहे हैं।

सम्मेलन में भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्यों, सीमाओं पर स्थिति, भीतरी इलाकों में स्थिति और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। इसके अलावा सम्मेलन में संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद, प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, आला प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और विभिन्न मौजूदा वैश्विक स्थितियों के प्रभाव के आकलन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन विद्या योग को विश्वपटल पर किया स्थापितः मुख्यमंत्री साय

रायपुर। योग आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वपटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपनाकर आरोग्य की प्राप्ति कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामयी समारोह में अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने संतों का अभिवादन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री साय ने योग आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष सिन्हा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिन्हा को छत्तीसगढ़ को जोड़ने और स्वस्थ रखने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जनसेवा को समर्पित उनका सामाजिक जीवन और सांगठनिक दायित्वों के लंबे अनुभव का लाभ योग आयोग के साथ ही प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। 2017 में स्थापित योग आयोग की

अब तक की यात्रा शानदार रही है और श्री सिन्हा के नेतृत्व में यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत में योग ऋषि-मुनियों की देन है और वे इस सुंदर परंपरा के संवाहक भी हैं। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही योग रूपी इस चेतना का विश्वभर में विस्तार हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने को मान्यता दी। साय ने कहा कि योग विश्वभर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ तन-मन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और भावी पीढ़ी को योग से जोड़कर इसका महत्व समझाना चाहिए।

योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग सभी के लिए है और सभी को जोड़ने का काम करता है। संगठन में काम करते हुए सदैव मैंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और आज मुझे योग आयोग के माध्यम से सभी को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सिन्हा ने कहा कि प्रकृति में अनेक महत्वपूर्ण संपदाएं उपलब्ध हैं, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ मानव संपदा है। मुख्यमंत्री ने मुझे मानव संपदा को स्वस्थ रखने का जिम्मा सौंपा है और इसे पूरा करने के लिए योग को जन-जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री नियमित योग करते हैं। उनकी ऊर्जा और कार्यक्षमता से आज सारी दुनिया वाकिफ है। सिन्हा ने योग की विश्वव्यापी लोकप्रियता और प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक संपत अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, डॉ. रामप्रताप सिंह, संजय श्रीवास्तव, महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज, पूज्य संत उदयनाथ जी महाराज, वासु देवानंद महाराज, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

हिमाचलः सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये मंजूरः सिंह

शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों समेत विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूंजी परिव्यय के तहत राज्य सरकार ने केंद्र से 1400 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से प्रथम चरण में 267 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने स्वयं कई बार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने और धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से चंबा और ऊना जिलों में तीन-तीन पुलों का निर्माण होगा। इसके अलावा, निगूलसरी-नाथपा सड़क पर भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए 54.37 करोड़ रुपये तथा कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चंबा-भरमौर सड़क के केरू पुल के पास भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए 40.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बांगड़ा-बनीखेत-चंबा-भरमौर भट्टी नाला पुल के समीप सड़क को टू-लेन बनाने और भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। ऊना जिले में बरना और बोरे वाली खड्ड पर पुलों के निर्माण समेत अन्य कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 24.27 करोड़ रुपये और स्वां नदी पर पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ठियोग बाईपास से गुजरने वाली कालका-शिमला-वांगतू सड़क के रखरखाव, सैंज-लूहरी-औट सड़क के संवेदनशील स्थानों की मरम्मत, ढली-ठियोग-नारकंडा-रामपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण, विभिन्न सड़कों की मैटलिंग एवं टारिंग तथा कलवर्ट निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोजगार की मांग को लेकर टेट अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एक झटके में लगभग 26 हजार शिक्षाकर्मियों ने नौकरियां खो दी है। इस फैसले के बाद गुरुवार को 2022 टेट (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) उम्मीदवारों ने नौकरी की मांग को लेकर विधाननगर में विकास भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सूत्रों के अनुसार, 2022 प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों ने डीएलएड ऐक्य मंच के बैनर तले गुरुवार को विकास भवन अभियान का आह्वान किया। नौकरी अभ्यर्थियों के वहां पहुंचते ही सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें भवन से काफी पहले ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हाथापाई हो गई जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विकास भवन के सामने से बलपूर्वक हटा दिया।

उत्तर रेलवे
ई-निविदा सूचना
वरिष्ठ मंडल वि. अभि./क. वि., डी. आर. एम. ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान : भाग-ए के संबंध में 25 केवी एसी ओएचई का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग, डीयूके सेक्शन पर बीबीडीई, बीजेडके, बीजेडजेटी, जीआरए, एमओवाई, टीआरआर, डीएचकेआर, डीपीपी, एसएचडीएम पर प्लेटफॉर्म का उन्नयन और बीबीडीई, बीजेडके, बीजेडजेटी, जीआरए स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म का विस्तार। भाग-बी: डीएसए-एसएमक्यूएल-एसआरई सेक्शन पर प्लेटफॉर्म का उन्नयन और विस्तार।
2	अनुमानित लागत : रु. 1,44,84,498.36/-
3	बयाना राशि : रु. 2,22,400/-
4	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अवधि : 15.04.2025 (10.30 बजे) से 29.04.2025 (15.00 बजे तक)
5	ई-निविदा समापन की अंतिम तथा ई-निविदा खुलने की तारीख और समय : 29.04.2025 (15.00 बजे)
6	निविदा छपाई की लागत : PH-53 (Capital)
7	वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है : www.ireps.gov.in

सं.: 01-क.वि.-नई दिल्ली-2025-26 दिनांक: 03.04.2025 1013/2025
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ

भू माफिया बन गया वक्फ बोर्ड, यूपी में माफियागीरी नहीं चलेगी: सीएम योगी

▶▶ मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपये की 181 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

प्रयागराज। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगा दी है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागीरी नहीं चलेगी, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने यहां प्रभु श्री राम एवं राजा निषाद से जुड़ी कथाओं तथा 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपये की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।

सीएम योगी ने श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि निषाद राज पार्क भगवान राम व निषाद राज की मित्रता का भव्य स्मारक है। सीएम योगी ने पार्क का निरीक्षण किया और कहा कि हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर भगवान राम ने कदम रखा था। निषाद राज ने मित्रता का धर्म निभाते हुए भगवान राम को गंगा पार कराई और चित्रकूट तक उनका साथ दिया। आज वही मित्रता बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच दिख रही है। यह इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि जहां भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, वहां घाटों का निर्माण और सुंदरीकरण होगा। महर्षि श्रृंगी और माता शांता के मंदिर का जीर्णोद्धार, संस्कृत विद्यालय, और विद्युत शोध गृह भी बनाया जाएगा। उन्होंने पार्क के रखरखाव और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने निषाद समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने निषाद राज वोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपये, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपये, और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। सीएम योगी ने कहा कि पहले यह पैसा बिचौलियों के पास जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इसे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। उन्होंने प्रशासन को निषाद समुदाय के लिए सीएनजी नौकाएं और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिए। जनसभा के दौरान भगवान राम के वेश में एक बालक ने शिव स्तुति सुनाई, जिससे सीएम योगी प्रभावित हुए और उन्होंने बच्चे को चॉकलेट देकर दुलारा। उन्होंने कहा कि यह प्रतिभा हमारी विरासत को आगे बढ़ाएगी।

सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ 2025 की सफलता प्रयागराज की नई पहचान का आधार बना है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज पर मां गंगा की असीम कृपा है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था, जो यहां नहीं पहुंचा? त्रिवेणी संगम में स्नान कर हर कोई पुण्य का भागीदार बना। उन्होंने कहा कि अब प्रयागराज को वाराणसी के बगल में बताने की जरूरत नहीं, यह अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज का अर्थ है महामिलन स्थल। यहां गंगा-यमुना-सरस्वती का मिलन है, तो भगवान राम और निषाद राज का मिलन भी है। मैं निषादराज जयंती और नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं।

सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की सफलता सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इतना भव्य आयोजन केवल राम भक्त और राष्ट्रनिष्ठ लोग ही कर सकते हैं। यह मां गंगा, भगवान राम, निषाद राज और द्वादश माधव की कृपा का परिणाम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में योगदान देने वाले प्रशिक्षित गाइड, नाविकों और होम स्टे संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुम्भ के बहाने प्रयागराज का चौतरफा विकास हुआ है। हनुमान जी कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर और द्वादश माधव कॉरिडोर ने प्रयागराज को नई पहचान दी है।

यह स्मार्ट सिटी से आगे एक प्रभावशाली शहर बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज शुरु की गई 579 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मेडिकल कॉलेज अपग्रेडेशन, पेयजल योजनाएं और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में प्रयागराज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सीएम योगी ने मां गंगा की अविरलता और निर्मलता पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारी विरासत और दिव्यता की प्रतीक है। नाविकों और गाइडों ने मेहनत से महाकुंभ को सफल बनाया और अपनी आजीविका को सशक्त किया। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगाई। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह बोर्ड भू माफिया बोर्ड हो गया है क्या, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का माफिया नहीं चल सकते हैं, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि निषाद राज के पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह-जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें प्रयागराज की पहचान मिटाने और माफियाओं को बढ़ावा देने में लगी थीं। हर जिले में माफिया पनप रहे थे। लेकिन हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर माफियाओं को विदा किया।

श्रृंगवेरपुर और प्रयागराज की पौराणिक भूमि पर कब्जे की कोशिशें नाकाम की गईं। सीएम ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', डॉ संजय कुमार निषाद, नरेन्द्र कुमार कश्यप, रामकेश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, महापौर उमेश गणेश केसरवानी, विधायक डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह, डॉ. केपी श्रीवास्तव, एमएलसी सुरेन्द्र चौधरी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, पूजा पाल समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

विकास और विरासत के संरक्षण के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध- सीएम

सीएम योगी ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को 138 करोड़ रुपये का ऋण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को अनुदान राशि का वितरण भी किया। सीएम योगी ने यहां मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नवीन आवास की चाबी देकर उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम योगी ने युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को स्वीकृति पत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि हर गरीब को आवास, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को पेंशन, और मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता मिल रही है। डबल इंजन की सरकार विकास और विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था: केशव मौर्य

कौशांबी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था। अपने गृह जनपद कौशांबी में नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता का दर्शन पूजन करने के बाद मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत में मौर्य ने कहा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा नए कानून के तहत जमीन को जांच के बाद ही वक्फ की संपत्ति माना जाएगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा इस कानून (वक्फ संशोधन विधेयक) का विरोध मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता चाहने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और यह कानून 90 प्रतिशत गरीब मुसलमानों के हित में है। मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक रोधी कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद को 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और मुस्लिम महिलाओं के हित में तीन तलाक कानून बनाया।

खदान में भरे पानी में डूबने से भाई-बहन की मौत

चित्रकूट। सिलिका सैंड की पुरानी खदान में भरे पानी में डूबने से गुरूवार को सगे भाई-बहन की मौत हो गई। मऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत परदवां गांव के निवासी गणेश भारतीय की 10 वर्षीय पुत्री कोमल अपने छोटे भाई आठ वर्षीय विकास के साथ घर के बाहर निकलकर खेल रहे थे। इस दौरान दोनों परदवां के मजरा कनभय में सिलिका खनन के पास पानी भरे गड्ढे के पास पहुंच गए और खेलते समय उसमें गिर गए।गहराई के चलते दोनों बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। गड्ढे के पानी में बच्चों को देख दोपहर में परिजन उन्हें निकालकर प्रयागराज के शंकरगढ़ अस्पताल पहुंचते, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि खेलते समय पुरानी खदान में जमा पानी में डूबने से दो बच्चों की मृत्यु हुई है। मामले में कार्रवाई कराई जा रही है।

राजपूत सेवा समिति ने सपा सांसद की सदस्यता खत्म करने की मांग उठाई

जौनपुर। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजपूत समाज का आक्रोश नहीं थमरहा है। राजपूत सेवा समिति के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में घूमकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

समिति के सदस्यों का कहना है कि सांसद का यह बयान न केवल राजपूत समाज का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। यह मुगलों से लड़ने वाले सभी वीर योद्धाओं का भी अपमान है। समिति के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारे देश के नायक, जिन्होंने मुगल आक्रांताओं से सौ बार बहादुरी से युद्ध किया ऐसे देश के महानायक को यदि सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन गद्दार कहते हैं तो देश का कोई स्वाभिमानी नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ऐसा बोलकर महान योद्धा राणा सांगा का अपमान किया है। उन्होंने संसद के सदन की गरिमा को भी कलंकित किया है। इसको समाज और समिति के पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगें। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। हमारी मांग है कि सांसद अपने इस बयान पर तुरंत माफी मांगें और इस्तीफा दें। इसको लेकर पूरे देश से करणी सेना 12 अप्रैल को राजस्थान ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन जायेगा।

ज्ञापन देने वालों में शशि मोहन सिंह क्षेम, शशि सिंह, प्रदीप सिंह सफायर, अजीत सिंह, शरद सिंह सहित राजपूत सेवा समिति के कई पदाधिकारी मौजूद थे।

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली, 15 अप्रैल को अगली सुनवाई

सुलतानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से संबंधित मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह के पेश न होने पर आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी।

उन्होंने बताया कि इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल नियत की है। पिछली सुनवाई 20 मार्च को थी। शुक्ला ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के प्रति कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किये जाने को लेकर मानहानि का वाद दायर कराया था।

वकील ने बताया कि पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था और कांग्रेस नेता ने फरवरी 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उनके मुताबिक, इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल को 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। शुक्ला ने बताया कि राहुल ने पिछले साल 26 जुलाई को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है।

उप जिलाधिकारी के आवास परिसर में मिला होमगार्ड के जवान का शव

अमेठी। जिले के गौरीगंज क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के आवास परिसर में एक कमरे से होमगार्ड के जवान का शव बरामद किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तहसील कैंपस स्थित उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के आवास परिसर में एक कमरे से बुधवार और बृहस्पतिवार की दरिमयानी रात होमगार्ड जवान राज किशोर (56) का शव बरामद हुआ। उसने बताया कि राज किशोर गौरीगंज थाना क्षेत्र के ही पनियार का रहने वाला था। वह गौरीगंज तहसील परिसर में ही उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मोहम्मद असलम के आवास पर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही वह मृत पाया गया। गौरीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पाण्डेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

उच्च न्यायालय से आजम खान को राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगी

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले के गंज थाना में 2007 में दर्ज एक मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न

्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने इस मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, अफसर खान नाम के एक व्यक्ति ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आजम खान के इशारे पर उसका घर ध्वस्त करा दिया गया था तथा पुलिस ने जांच के बाद 2007 में ही अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी थी जो संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है। अफसर खान की 2017 में मृत्यु हो गई और उसके बेटे जुल्फिकार खान ने पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की जिस पर रामपुर

के विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) ने 21 जनवरी 2025 को इस मामले की आगे और जांच करने का आदेश पारित किया था। आजम खान के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के 18 साल बाद यह विरोध याचिका दाखिल की गई। इस मामले में 10 जुलाई, 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने जांच के बाद सात दिसंबर 2007 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किए गए और इसके बाद यह मामला लंबित रहा और अंतिम रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उनके मुताबिक, शिकायतकर्ता अफसर खान का 18 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया जिसकी सूचना अदालत को 16 जनवरी 2023 को दी गई और आपत्ति दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया।

आजम खान के वकील ने बताया कि अफसर खान के पुत्र जुल्फिकार खान ने सात दिसंबर 2024 को विरोध याचिका दायर की जिस पर जुल्फिकार खान का पक्ष सुनने के बाद मामले में आगे और जांच करने का आदेश 21 जनवरी 2025 को पारित किया गया। राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए अदालत ने बुधवार को पारित अपने आदेश में अगली सुनवाई की तिथि पांच मई 2025 तय की और आदेश दिया कि तब तक याचिकाकर्ता को उक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने की वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना, सरकार पर विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाया

वाराणसी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित करने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार की आलोचना की और इसे विपक्ष की बात सुने बगैर जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। राय ने सरकार पर मनमाने तरीके से काम करने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। वक्फ (संशोधन) विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हुआ और बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया गया। राय ने कहा कि वक्फ विधेयक जल्दबाजी में लाया गया।

सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। जो चाहा, वह किया। सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए वादे किये लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए राय ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है और वह जो चाहे कर रही है। चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो या वक्फ विधेयक, सरकार लोगों की चिंताओं की अनदेखी करते हुए एकतरफा फैसले ले रही है। राय ने अमित शाह की उस टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अपने घर से ही होता है।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा में केवल अपने नेताओं की चापलूसी करने वालों को ही बढ़ावा दिया जाता है, जबकि मेहनती और योग्य कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। असली कार्यकर्ता घर पर ही पकौड़े बनाते रह जाते हैं। राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की वाराणसी यात्रा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वह प्रयागराज में महाकुंभ में क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि भागवत हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करते हैं, फिर भी वह सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में नहीं गए। इससे उन लोगों पर गंभीर सवाल उठते हैं जो हिंदुत्व के अलमबरदार होने का दावा करते हैं।

चिकित्सक और नर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत

हरदोई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शाहाबाद में भर्ती प्रसूता और उसके बच्चे की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और नर्स पर रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। वहीं, घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जच्चा और बच्चा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम सुहागपुर निवासी कमल किशोर अपनी गर्भवती पत्नी रीता (20) को लेकर गुरुवार की सुबह 3 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। जहां स्टाफ नर्स दीपिका ने उसे भर्ती कर लिया। कमल किशोर के अनुसार, उसने स्टाफ नर्स से पूछा कि यदि कोई परेशानी या दिक्कत हो तो वह प्राइवेट नर्सिंग होम चला जाए। आरोप है कि स्टाफ नर्स दीपिका ने 3000 रुपये की मांग की और कहा कि मुझे पैसा दे दो, मैं यहीं आराम से डिलीवरी करवा दूंगी। गुरुवार सुबह 9 बजे रीता के लड़का पैदा हुआ और दोनों की मौत हो गई। उसके बाद स्टाफ नर्स ने उसे हरदोई जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जच्चा-बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। जिसके बाद स्टाफ नर्स दीपिका अस्पताल से फरार हो गई। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर प्रवीण दीक्षित से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रात में रिजवान खां और स्टाफ नर्स दीपिका की ड्यूटी थी। इसलिए उनसे बात कर लें। डॉ रिजवान खां ने बताया कि इलाज के दौरान हालत गंभीर होने पर प्रसूता को जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया परंतु एम्बुलेंस विलम्ब से आई, जिसकी बजह से जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई। इंस्पेक्टर शिव गोपाल ने बताया कि पुलिस ने जच्चा और बच्चा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बुद्धा देवी का ऐसा मंदिर, यहां प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं हरी सब्जियां

कानपुर। देशभर में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में ऐसे तमाम देवी मंदिर हैं। जो अपनी प्राचीन मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक हटिया इलाके में स्थापित करीब 110 साल प्राचीन बुद्धा देवी का मंदिर है, जिसकी खासियत यह है कि यहां पर देवी के समक्ष प्रसाद के रूप में हरी सब्जियां चढ़ाई जाती हैं।

ऐसी मान्यता है कि हरी सब्जियां चढ़ाने से भक्तों का परिवार भी हरा भरा रहता है। बाकी मंदिरों की तरह यहां की देखरेख कोई पुजारी नहीं बल्कि रघुवीर माली करते हैं। गुरुवार उन्होंने मंदिर को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। नवरात्रि के दिनों में देवी मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो शहर में कई देवी मंदिर है। जिनसे उनका अपना इतिहास भी जुड़ा है। इन्हीं में से एक हटिया इलाके में स्थापित बुद्धा देवी का मंदिर है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी सकरे रास्ते से होकर सकरे गुजरना पड़ता है। यहां विशेष तौर पर बुधवार को भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। जो नवरात्रि के दिनों में कई गुना बढ़ जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर आए हुए श्रद्धालु देवी को हरी-भरी सब्जियों जैसे लौकी, भिंडी, बैगन, नीबू, टमाटर इत्यादि का भोग लगाते हैं।

मंदिर की देखरेख करने वाले रघुवीर माली ने बताया कि जिस जगह पर यह मंदिर बना हुआ है। सैकड़ो साल पहले यहां पर सब्जियों का बगीचा हुआ करता था। जिसकी देखरेख उनके पूर्वजों द्वारा की जाती थी। माली के पूर्वज बुद्धू को लगातार एक सप्ताह तक सपने में देवी मां आईं और बोली कि मुझे इस बगीचे से बाहर निकालो। बार-बार आ रहे सपने से परेशान होकर एक दिन आखिरकार उन्होंने देवी की बताई हुई जगह पर खुदाई शुरू कराई।

कई दिनों तक खुदाई करने के बाद देवी की प्राप्ति हुई। इसके बाद वहीं पर उन्हें स्थापित कर उनका नाम बुद्धा देवी रख दिया गया। तभी से देवी को हरी सब्जियां चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर में बड़ी संख्या में किसान भी देवी को हरी सब्जियों का प्रसाद चढ़ाने आते हैं। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देवी के खुश होने से उनकी फसल की पैदावार भी हरी-भरी होगी।

वक्फ संशोधन बिल : मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने कहा, धन्यवाद मोदी जी

झांसी। वक्फ विधेयक संशोधन बिल लोक सभा में पास होने पर गुरूवार को मुस्लिम समुदाय के पुरुषों व महिलाओं ने हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। खुशी जाहिर करते हुए मिठाई वितरित की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। महिलाओं ने अपनी भावनाएं पट्टिकाओं पर प्रदर्शित करते हुए लिखा वक्फ बिल संशोधन के लिए धन्यवाद मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के नेतृत्व में कई भाजपा नेताओं व मुस्लिम समुदाय के पुरुष एवं महिलाओं ने खुशी व्यक्त की। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मिठाइयां बांटी गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पास होने से आर्थिक संकट से जूझ रहे तथा अन्य मुस्लिमों को भी इसका लाभ और सम्मान मिलेगा। इस बिल के पास होने से जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को खराब लग रहा है। वक्फ विधेयक पास होने से मुस्लिम समुदाय के हित में कार्य होगा, उनका विकास होगा। इस दौरान भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, व्यापारी नेता मनमोहन, पुनीत अग्रवाल सहित कई पार्टी नेता और मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहें।

कृषि मंत्री ने किया विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

योगी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं: शाही

देवरिया। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को गति देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार जनपद देवरिया के ग्राम कोटवा बावन में प्राचीन मां दुर्गा मंदिर के सुंदरीकरण, नगर पंचायत हेतिमपुर में स्टडी सेंटर एवं डिजिटल लाइब्रेरी, साथ ही पार्क व जिम से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांव, गरीब, किसान और युवा सरकार की प्राथमिकता में है।

उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, वे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की मंशा है कि गांवों और छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ताकि कोई भी युवा, किसान या नागरिक संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों को उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाएं, अनुदान और नई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

आकांक्षी नगर योजना के तहत नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड संख्या-8 में स्टडी सेंटर एवं डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी कृषि मंत्री ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। इसमें डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि यह प्रयास युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में सहायक होगा और उनके भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी क्रम में, नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड संख्या-6 में पार्क एवं जिम के निर्माण कार्य की

आधारशिला भी रखी गई। इस पार्क में टहलने के लिए ट्रैक, ओपन जिम, ग्रीन एरिया और अन्य सुविधाएं होंगी, जिससे नागरिकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, और इसी दिशा में यह पार्क एवं जिम एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि जनपद देवरिया के कोटवा में स्थित दुर्गा देवी स्थल के पर्यटन विकास कार्य हेतु 97.20 लाख रुपये की स्वीकृत लागत निर्धारित की गई है।

इस परियोजना का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत यात्री निवास, स्टोन फ्लोरिंग, सबमर्सिबल पंप बोरिंग सहित, पाथवे, स्टोन बेंच, विद्युतीकरण, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट ब्लॉक, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। मंदिर परिसर के सुंदरीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को परखा। एक दिवसीय दौरे पर शहर में आए मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और उससे जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी कार्यक्रमों की तैयारी अंतिम रूप से समय से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विशेष तौर पर उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करा लिए जाने के लिए निर्देशित किया।

प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने के साथ ही अन्य सभी तैयारी समय से पूर्व करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभा स्थल पर आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौके पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था के साथ ही साथ छाया एवं शौचालय आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रधानमन्त्री के प्रस्तावित जनपद आगमन के दौरान की गयी तैयारियों को बिन्दुवार प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित तथा शिलान्यास होने वाले

प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया की सभा स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, सफाई कर्मियों की ड्यूटी, मोबाइल टॉयलेट, पीने का पानी, लंच पैकेट्स, ट्रैफिक हेतु भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान पुलिस की तैयारियों समेत सभी अभियानों की प्रगति मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसके पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल मेंहदीगंज का निरीक्षण किया। कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल तथा जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कार्यक्रम स्थल पर किए जा रहे व्यवस्थाओं के बाबत मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर कतिपय स्थानों पर जमीन धंसने की घटना का संज्ञान लिया। इसके गुणवत्ता की जांच कराते हुए शीघ्र मरम्मत कराए जाने का निर्देश दिया। वरुणा रिवर फ्रंट के सुंदरीकरण कार्यों के संबंध में शीघ्र ठोस कार्ययोजना बनाकर तद्नुसार कार्य किए जाने का निर्देश दिया। नेशनल फोरेंसिक विश्वविद्यालय के विस्तार कैंपस के लिए उपयुक्त स्थल चयन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाने तथा इसमें आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', पूर्व मंत्री तथा विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, पूनम मौर्य, अशोक तिवारी, हंसराज विश्वकर्मा, डॉ सुनील पटेल, सौरभ श्रीवास्तव, अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, डीआईजी मोहित गुप्ता, आदि भी मौजूद रहे।

अब नहीं होंगे नैनीताल नगर पालिका के लेकब्रिज एवं कार पार्किंग के ठेके

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को नैनीताल नगर पालिका के लेकब्रिज चुंगी एवं कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की ओर से एक अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी एवं कार पार्किंग के ठेके अब नहीं होंगे। इनका संचालन नगरपालिका सहायता समूहों की मदद से स्वयं करेगी।

नगर पालिका ने लेकब्रिज चुंगी व डीएसए, कार पार्किंग व मेट्रोपोल कार पार्किंग के टेंडर पहले ही निरस्त कर दिए हैं। नगर पालिका अब नैनीताल में आने वाले वाहनों से 'नैनीताल इंट्री टेक्स' नाम से बढ़ा हुआ शुल्क लेगी और शहर में प्रवेश करने वाले तीनों मार्गों में टैक्स वसूली बूथ भी बनाए जाएंगे। इस संबंध में नगर पालिका की ओर से पालिका बायलॉज में संशोधन भी किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दीवान फर्त्याल, सुमित जेट्टी व ठाकुर इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी।

सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दीपक गोस्वामी भी कोर्ट में मौजूद थे। नगर पालिका की ओर से लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के संचालन के संबंध में नगर पालिका की ओर से विस्तृत जवाब दिया गया। कोर्ट ने नगर पालिका के जवाब के बाद निर्देश दिया कि नगर पालिका 'नैनीताल इंट्री टेक्स' केवल 'यूपीआई स्कैनर कोड' के माध्यम से वसूल करेगी। ताकि चुंगी वसूली बूथों में पैसो के लेनदेन के कारण अनावश्यक जाम से बचा जा सके। इस मामले में नगर पालिका की ओर से नेटवर्क में कमी के कारण ऑन लाइन चुंगी वसूली प्रक्रिया में दिक्कत होने का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।

सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पालिका में कर अधीक्षक, सफाई अधीक्षक, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, लेखाकार, सहायक लेखाकार सहित आठ महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने सचिव, शहरी विकास से इन पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं।

पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की कैद

हमीरपुर। अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर जानमाल की धमकी देने के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी विजय राजपूत को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ति पिता ने 12 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि जनपद महोबा के महोबकंठ थानाक्षेत्र के परावारी गांव निवासी दोषी उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर कहीं ले गया और उसके साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी विजय को सजा सुनाई है।

विद्यालयों में नये विषय खोलने को प्रस्ताव भेजें अधिकारी: मंत्री धन सिंह रावत

घटती छात्रसंख्या को जांच समिति गठित, एक सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

देहरादून। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नये विषय खोले जायेंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या में गिरावट को देखते हुए विभागीय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री रावत ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेशभर के विद्यालयों में नये विषयों की मांग को ध्यान में रखते हुए महानिदेशालय को शीघ्र प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अभिभावक संघों की ओर से समय-समय पर नये विषय खोले जाने की मांग की जाती रही है। बैठक में उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव भी भेजने को कहा है। इसके अलावा प्रत्येक विकासखण्ड में प्रस्तावित कलस्टर विद्यालय, जीर्ण-शीर्ण स्कूलों सहित डी व सी श्रेणी के विद्यालयों के निर्माण के प्रस्ताव भी इसी माह तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये जिन जनपदों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इसके अलावा डॉ. रावत ने अधिकारियों को सभी विद्यालयों में पेयजल, विद्युत, फर्नीचर, कंप्यूटर और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, किताबों, स्कूल ड्रेस और मनमानी फीस वृद्धि को लेकर विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर पर दर्ज शिकायत का शीघ्र निस्तारण करने को भी अधिकारियों को कहा।

रुड़की क्षेत्र में विकसित की जा रही तीन अनधिकृत कॉलोनियां ध्वस्त

हरिद्वार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को रुड़की क्षेत्र में विकसित की जा रही तीन अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया।

संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की व संयुक्त सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के निर्देशन में शेरपुर, रुड़की में अब्दुल कयूम द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि क्षेत्रफल में, गंगोत्रीपुरम शनिदेव मंदिर के पीछे रुड़की में कमल किशोर द्वारा लगभग 8 बीघा भूमि क्षेत्रफल में तथा गुलमोहर के पीछे मलकपुर लतीफपुर, रुड़की में शादाब द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित करने हेतु किए गए अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया। स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के फलस्वरूप सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के आदेश पर निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया। संबंधितों को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: राधा रानी को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह हटाने की मांग में विचाराधीन सिविल वादों की सुनवाई के दौरान वादी के रूप में राधा रानी को भी शामिल करने की मांग में अर्जी दी गई। साथ ही शाही मस्जिद को विवादित ढांचा कहे जाने की भी मांग की गई, जिस पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति की। सिविल वादों की अगली सुनवाई की तिथि छह मई तय की गई है। सभी सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा कर रहे हैं।

एक वाद में भविष्य की कार्यवाही में और अदालत के समक्ष लम्बित अन्य संबंधित मामलों में 'शाही ईदगाह मस्जिद' के स्थान पर 'विवादित ढांचा' के उपयोग की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2025 को वादी द्वारा मांगे गए कुछ संशोधनों की

अनुमति दी। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन पर कब्जा करने और मंदिर की बहाली के लिए 18 मुकदमें दायर किए हैं जो पहले स्थायी निषेधाज्ञा से अलग थे। एक अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने हिंदू उपासकों के मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदनों को खारिज कर दिया था और माना था कि हिंदू उपासकों के सभी मुकदमे सुनवाई योग्य थे।

एक अगस्त के आदेश में अदालत ने यह भी माना कि ये मुकदमें परिसीमा अधिनियम, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं थे, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक संरचना के रूपांतरण पर रोक लगाता है। 23 अक्टूबर 2024 को उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के संबंध में दायर सभी मुकदमों को समेकित करने के उच्च न्यायालय के 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया।

यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब-युग की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है। जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।

एयर वाटर इंडिया के निदेशक काजुया हिगुची ने किया देसंविवि का शैक्षिक भ्रमण

हरिद्वार। एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक काजुया हिगुची अपनी टीम के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शैक्षिक और आध्यात्मिक वातावरण का अध्ययन किया। युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में चल रहे स्वावलंबन व रचनात्मक कार्यों की कार्यप्रणाली को बारिकी से परखा।

हिगुची ने देसंविवि के प्रतिकुलपति डा. चिन्मय पण्ड्या से भेंट की और प्रौद्योगिकी, सतत विकास और समग्र शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों ने आध्यात्मिकता और उद्योग जगत का समन्वय समाज के संतुलित एवं दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर अपने विचार साझा किए।

हिगुची की इस यात्रा ने वैश्विक संगठनों और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच सहयोग की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह विश्वविद्यालय की परिवर्तनकारी दृष्टि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सशक्त करता है, बल्कि ऐसे सहयोगों को भी प्रेरित करता है जो शिक्षा, संस्कृति और नवाचार के माध्यम से सामाजिक उत्थान में सहायक हो सकते हैं।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी भी अफवाहों पर ना दें ध्यान: डीसीपी सेंट्रल

कानपुर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के मद्देनजर शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से वार्ता पुलिस चौकी सद्भावना परेड के परिसर में रखी गई। यह जानकारी गुरूवार को पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने दी।

डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि मुस्लिम धर्म गुरुओं से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अफवाहों से बचाव और जागरूकता पर जोर देते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक या गलत जानकारी को बिना पुष्टि किए साझा न करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है।

डीसीपी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से बात करने पर आश्वास्त किया है कि प्रशासन को हम पूरा सहयोग देंगे और समाज में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस मौके पर अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम मुस्लिम धर्मगुरु उपस्थित रहे।

BHEL ने किए हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर

हरिद्वार। बीएचईएल ने भादला-फतेहपुर एलसीसी एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन के साथ-साथ भादला और फतेहपुर में एसी ट्रांसमिशन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भेल ने हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम साझेदारी में राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

जिसके अंतर्गत 6,000 मेगावाट, 800 केवी, बाई-पोल और द्विदिशात्मक हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) टर्मिनल्स को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाएगा। जिससे राजस्थान के भादला से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और परिवहन केंद्र फतेहपुर तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण होगा। यह एचवीडीसी लिंक परियोजना वर्ष 2029 तक पूरी हो जाएगी तथा 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 500 गीगावाट बिजली प्राप्त करने के राष्ट्रीय मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

बीएचईएल हरिद्वार के संचार एवं जनसंपर्क प्रमुख संजय पंवार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बीएचईएल को आवंटित चौथी अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (यूएचवीडीसी) ट्रांसमिशन परियोजना अनुबंध है। कंपनी ने पहले से ही उत्तर-पूर्व आगरा 800 केवी, 6,000 मेगावाट, मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी लिंक और 800 केवी 6,000 मेगावाट रायगढ़-पुगलूर एचवीडीसी लिंक का निष्पादन किया है और वर्तमान में हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एबीबी) के साथ संयुक्त रूप से 800 केवी, 6,000 मेगावाट खावड़ा-नागपुर एचवीडीसी लिंक का निष्पादन कर रही है।

इस परियोजना के लिए अन्य उपकरणों और प्रणालियों के अतिरिक्त बीएचईएल अपने भोपाल प्लांट से कनवर्टर ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, फिल्टर बैंक कैपेसिटर, एमवी स्विचगियर और इन्सटूमेंट ट्रांसफॉर्मर तथा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बेंगलुरु से थाइरिस्टर वाल्व की आपूर्ति करेगा। इन वाल्वों का उपयोग भादला में एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, कंपनी का ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप फतेहपुर टर्मिनल पर विशाल आकार की 765 केवी/400 केवी बिजली निकासी प्रणाली तथा भादला और भादला एक्सटेंशन में 400 केवी एसी सब-स्टेशन का डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना करेगा।

भारतीय ग्रिड में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों की उत्पत्ति की शुरुआत से ही, बीएचईएल भारत में प्रमुख एचवीडीसी परियोजनाओं जैसे रिहंद-दादरी, चंद्रपुर-पड़घे, बलिया-भिवाड़ी, उत्तर पूर्व-आगरा और रायगढ़-पुगलुर एचवीडीसी लिंक के निर्माण से जुड़ा हुआ है और 800 केवी तक के एचवीडीसी उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं।

PPF खातों में नॉमिनी से जुड़ी जानकारी में बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा: वित्त मंत्री

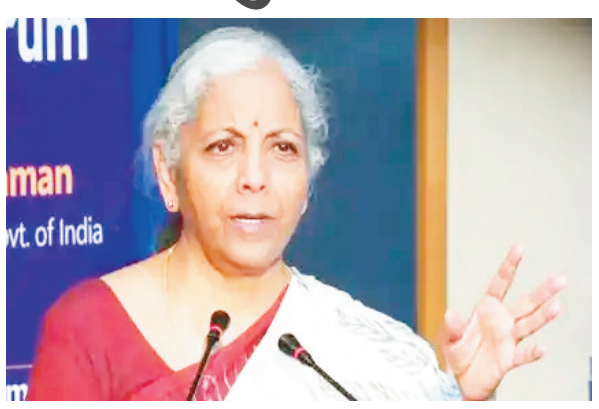

नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए 'नॉमिनी' बनाने, जोड़ने या उसमें कोई बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अधिसूचना के जरिए कई आवश्यक बदलाव किए हैं। लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में लिखा, हाल ही में पीपीएफ खातों में 'नॉमिनी' व्यक्ति के विवरण को जोड़ने या संशोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा शुल्क लेने की जानकारी मिली है। दरअसल 'नॉमिनी' के पास मूल खाताधारक की राशि पर कानूनी अधिकार होता है। सीतारमण ने कहा कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी तरह के शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल की राजपत्र अधिसूचना के जरिए सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राजपत्र अधिसूचना में सरकार के द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में जमाकर्ताओं के पैसे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान एवं सुरक्षा लॉकर के भुगतान के लिए अधिकतम चार लोगों को 'नॉमिनी' बनाने की अनुमति है। इस विधेयक में एक और बदलाव बैंक में किसी व्यक्ति के ''पर्याप्त कर'' शब्द को फिर से परिभाषित करने से संबंधित है। इस सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा दर को लगभग छह दशक पहले तय किया गया था।

ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन करेगा भारत : वित्त राज्य मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत पारस्परिक टैरिफ वृद्धि और देश पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आईआईएम, अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित 'प्रथम अंतरराष्ट्रीय पेंशन शोध सम्मेलन' में कहा कि भारत पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव की समीक्षा और आकलन करेगा। पंकज चौधरी ने कहा कि ट्रंप के लिए यह अमेरिका पहले है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह भारत पहले है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।₹ वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका की शुल्क बढ़ोतरी और देश पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

भारत सुरक्षित हाथों में है, जनादेश सरकार के साथ : जितिन प्रसाद

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बृहस्पतिवार को भारत की स्टार्टअप तंत्र के माध्यम से 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के लिए तत्परता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश एक मजबूत और स्थिर सरकार के सुरक्षित हाथों में है। राज्यमंत्री प्रसाद ने स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण के उद्घाटन के दौरान कहा कि जनादेश सरकार के साथ है।

उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, नवप्रवर्तकों का स्टार्टअप समुदाय, तथा आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए नए विचार, भारत को सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन लाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे। प्रसाद ने कहा कि आपको दुनिया को बताना होगा कि भारत चुनौतियों के लिए तैयार है। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास कौशल है। हमारे पास चुस्त सरकार है भारत सुरक्षित हाथों में है। जनादेश सरकार के साथ है। नीतियां मजबूत और स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप बहुत बढ़िया मूल्य निर्माता हैं। मंत्री ने कहा कि न केवल हितधारक और सरकार बल्कि आम आदमी भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र या विकसित भारत बनने का अपना सपना पूरा करे।

प्रसाद ने कहा कि अब चर्चाओं को वातानुकूलित कमरे की बैठकों से आगे बढ़ाकर जमीनी स्तर पर ऐसे मामलों पर ले जाना चाहिए, जो वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि 'सक्रिय सरकार सुनती है'। तीन से पांच अप्रैल तक चलने वाले 'स्टार्टअप महाकुंभ' में 50 से अधिक देशों की स्टार्टअप कंपनियां, निवेशक और उद्योग जगत के दिग्गज भाग ले रहे हैं।

ट्रंप की शुल्क घोषणा के बाद IT, प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 322 अंक टूटा

मुंबई। स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 322 अंक टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली तथा वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से बाजार नुकसान में रहा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 322.08 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,295.36 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान एक समय यह 809.89 अंक तक लुढ़क गया था। हालांकि, बाद में औषधि शेयरों में तेजी से बाजार नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने में सफल रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.25 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,250.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी एक समय 186.55 अंक तक लुढ़क गया था। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट आई। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में पावरग्रिड, सन फार्मास्युटिकल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, टाइटन, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। छोटी कंपनियों से जुड़े बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में 0.76 प्रतिशत की तेजी रही जबकि मझोली कंपनियों से संबंधित मिडकैप 0.31 प्रतिशत मजबूत हुआ। बीएसई में 2,809 शेयरों में तेजी रही, जबकि 1,175 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

139 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क दरों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,538.88 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,808.83 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 592.93 अंक चढ़ा था जबकि एनएसई निफ्टी में 166.65 अंक की तेजी आई थी।

रुपया शुरुआती नुकसान से उबरा 22 पैसे चढ़कर 85.30 प्रति डॉलर पर

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया अपने शुरुआती नुकसान से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे के उछाल के साथ 85.30 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने के कारण हुआ। शुरुआती कारोबार में घरेलू मुद्रा को झाटका लगा लेकिन जल्द ही इसने अपनी खोई जमीन फिर हासिल कर ली और दिन का अंत में यह सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत, अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। भारत के प्रतिद्वंद्वी देशों को अधिक ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया 85.77 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 85.30 के उच्चस्तर और 85.78 प्रति डॉलर के निचले स्तर को छूने के बाद कारोबार के अंत में 85.30 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ जो कल के बंद भाव के मुकाबले 22 पैसे का उछाल है।

सोना 200 रुपये की बढ़त के साथ 94,350 रुपये के नए शिखर पर, चांदी 1,000 रुपये टूटी

नई दिल्ली। आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट की सतत लिवाली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 94,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 94,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा था।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 200 रुपये बढ़कर 93,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी की कीमत बुधवार के बंद स्तर 1,01,500 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,000 रुपये टूटकर 1,00,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। एलकेपी सिक्योरिटीज में उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जिंस और मुद्रा जतिन त्रिवेदी ने कहा कि जवाबी शुल्क के प्रभाव से सुबह के सत्र में सोने में शुरुआती तेजी देखी गई, लेकिन जल्द ही कीमतों में मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना 43.39 डॉलर या 1.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,089.64 डॉलर प्रति औंस रह गया। बुधवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 60 से अधिक देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद यह 3,167.71 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया था। अबन्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) चिंतन मेहता के अनुसार, निवेशक ट्रंप की नई शुल्क नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनके संभावित प्रभाव का बारीकी से आकलन करेंगे।

मेहता ने कहा कि इसके अलावा, बाजार का ध्यान साप्ताहिक अमेरिकी बेरोजगारी दावों और बृहस्पतिवार को देर से जारी होने वाले सेवा पीएमआई आंकड़ों पर रहेगा, जो बढ़ते व्यापार तनाव के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में और जानकारी दे सकते हैं।

सेमीकंडक्टर को अमेरिकी शुल्क से छूट उसकी आधारभूत भूमिका को दर्शाता है: उद्योग

नई दिल्ली। सेमीकंडक्टर उद्योग संगठन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से सेमीकंडक्टर को छूट' दी गई है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसकी आधारभूत भूमिका को दर्शाता है। आईईएसए ने साथ ही कहा कि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जवाबी शुल्क भारत के समग्र निर्यात के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की भागीदारी की शर्तों को फिर से परिभाषित करते हुए व्यापक जवाबी शुल्क की घोषणा की।

ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए इस दिन को अमेरिका का मुक्ति दिवस करार दिया। अमेरिका ने भारत से आयात पर 27% शुल्क लगाने की घोषणा की है। आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा कि शुल्क बढ़ोतरी की गति तथा पैमाने से वैश्विक वृद्धि धीमी हो सकती है, बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है और दुनिया भर में व्यवसायों पर दबाव पड़ सकता है। चांडक ने कहा कि हालांकि भारत कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये शुल्क संभावित रूप से घरेलू उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं, व्यापार प्रवाह को बाधित कर सकते हैं और लाभ मुनाफे को कम कर सकते हैं।

भू-राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य के विकास के साथ भारत को जोखिमों को कम करने और वैश्विक व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए व्यापार कूटनीति, घरेलू नीतिगत बदलावों और औद्योगिक लचीलेपन का लाभ उठाते हुए रणनीति बनानी चाहिए। चांडक ने कहा कि सेमीकंडक्टर व दवा कंपनियों को शुल्क से छूट दी गई है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं व सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनकी आधारभूत भूमिका को मान्यता देता है। अमेरिका ने भारत से आयात पर 27% शुल्क लगाया है, जबकि चीन , यूरोपीय संघ, वियतनाम और ताइवान सहित कई देशों के लिए शुल्क की ऊंची दरें तय की गई हैं।

भारतीय बाजार में कम लागत वाला इस्पात आयात बढ़ने की आशंका : आईएसएसडीए

नई दिल्ली। उद्योग निकाय आईएसएसडीए ने गुरुवार को कहा कि भारत कम लागत वाले इस्पात आयात के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा क्योंकि अमेरिका के शुल्क लगाने से प्रभावित देश अपनी खेप को घरेलू बाजार में भेज सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए 'उच्च' शुल्क के जवाब में लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत के लिए, अमेरिका ने 27% का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाता है। अमेरिका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य देश के व्यापार घाटे को कम करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि, वाहन और वाहन कलपुर्जा तथा इस्पात एवं एल्युमीनियम की वस्तुएं पहले से ही धारा 232 के तहत 25 % शुल्क के अधीन हैं और ये वस्तुएं नवीनतम आदेश में शामिल नहीं हैं। इनपर शुल्क लगाने की घोषणा ट्रंप के 26 मार्च, 2025 के आदेश में की गई थी।

अमेरिकी जवाबी शुल्क भारतीय आभूषण व रत्न निर्यात के लिए बड़ा झटका: जीजेईपीसी

मुंबई। शीर्ष उद्योग निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका का जवाबी शुल्क भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही उसने सरकार से इस क्षेत्र के दीर्घकालिक हित को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों पर भारी बोझ पड़ेगा। जीजेईपीसी ने कहा कि दीर्घावधि में हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया आकार देते हुए देखते हैं। अल्पावधि में हम अमेरिकी बाजार में भारत के मौजूदा 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बनाए रखने में चुनौतियों का अनुमान लगाते हैं। बयान में कहा गया कि हम भारत सरकार से दोनों देशों (भारत और अमेरिका) के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह शुल्क मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका भारत से 11.58 अरब अमेरिकी डॉलर के रत्न एवं आभूषण आयात करता है। वहीं भारत को 5.31 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 16.89 अरब अमेरिकी डॉलर का है।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में प्राकृतिक व प्रयोगशाला में बने एवं पॉलिश किए गए हीरे, सोने तथा प्लैटिनम के आभूषण, चांदी के आभूषण, नकली आभूषण, कच्चे हीरे, कच्चे एलजीडी, कच्चे रंगीन रत्न, सोने की छड़, चांदी की छड़ तथा प्लैटिनम की छड़ और रंगीन रत्न आदि शामिल हैं।

अमेरिकी शुल्क भारतीय निर्यातकों को प्रभावित करेगा लेकिन दूसरों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर : फियो

नई दिल्ली। निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर लगाया गया 27 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क निःसंदेह घरेलू निर्यातकों के लिए चुनौती है, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा कि शुल्क के बावजूद भारत में परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, प्लास्टिक तथा फर्नीचर सहित कुछ क्षेत्रों में निर्यात में बदलाव हो सकता है, जिससे कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई हो सकती है।

रल्हन ने कहा कि हालांकि ये शुल्क चुनौतियां पेश करते हैं, लेकिन भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से अनुकूल बनी हुई है। मिसाल के तौर पर वियतनाम में 46 प्रतिशत, चीन में 34 प्रतिशत और इंडोनेशिया में 32 प्रतिशत शुल्क है, जिससे भारत वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा म्यांमा जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है।'' उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का समय पर निष्कर्ष इन शुल्कों को कम करने और भारतीय निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। रल्हन ने कहा कि इस तरह के समझौते से शुल्क चुनौतियों को हल करने के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित हो सकता है, जिससे एकतरफा व्यापार उपायों या जवाबी शुल्कों के आसार कम हो जाएंगे।

भारत और अमेरिका इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य इस वर्ष शरद ऋतु तक पहले चरण को पूरा करना तथा 2030 तक वस्तुओं व सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत से आयातित उत्पादों पर पहले से ही अमेरिका में इस्पात, एल्युमिनियम और वाहन क्षेत्र पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है। शेष उत्पादों के लिए भारत पांच से आठ अप्रैल के बीच 10 प्रतिशत के 'बेस लाइन' शुल्क के अधीन है। फिर नौ अप्रैल से शुल्क देश-विशिष्ट 27 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। अमेरिका के साथ भारत का 2023-24 में माल के मामले में व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था।

फार्मा पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ छूट का विशेषज्ञों ने किया स्वागत, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर

नई दिल्ली। भारतीय दवा निर्यात को डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी गई है। उद्योग जगत के जानकारों ने गुरुवार को इस कदम का स्वागत किया और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों ने इस टैरिफ छूट के लिए लागत प्रभावी और जीवन रक्षक भारतीय जेनेरिक दवाओं के महत्व का हवाला दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद बुधवार को जारी व्हाइट हाउस फैक्टशीट में कहा गया कि फार्मास्युटिकल्स को टैरिफ से छूट दी गई है। भारतीय दवाएं, विशेष रूप से जेनेरिक, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की लागत को कम करने में मदद करती हैं, जो पहले से ही दुनिया में सबसे महंगी दवाओं में शामिल हैं। भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत हैं, जिसमें मिशन-500 पहल के तहत व्यापार को दोगुना कर 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का साझा दृष्टिकोण है। फार्मास्युटिकल्स इस साझेदारी का आधार बने हुए हैं, क्योंकि भारत सस्ती दवाओं की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित कर वैश्विक और अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल्स को टैरिफ से छूट दी गई है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा में लागत प्रभावी, जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका भारत से फार्मास्युटिकल्स का सबसे बड़ा आयातक है, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान 8.73 बिलियन डॉलर मूल्य के उत्पाद लाया। आईबीईएफ ने कहा कि भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात का 31.5 प्रतिशत अमेरिका को गया। जैन ने कहा कि भारतीय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश दवा आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करेगा और सभी के लिए सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ मेडिकल डिवाइस के डेटा के अनुसार, 2023-24 में, भारत का अमेरिका को मेडिकल डिवाइस निर्यात 714.38 मिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका से भारत में आयात 1,519.94 मिलियन डॉलर के साथ काफी अधिक था। एआईएमईडी के फोरम कॉर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "अमेरिका को भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्यात पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।

नाथ ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका के लिए भारत लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य-उच्च मात्रा वाले चिकित्सा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। हालांकि, यह नया टैरिफ संभवतः भारतीय चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। हमें उन स्थितियों का पता लगाना होगा, जहां अमेरिका किसी एक देश पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने घरेलू विनिर्माण को मजबूत कर और विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम कर स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

कनाडा और मैक्सिको में संयंत्र लगाने वाले भारतीय विनिर्माताओं पर अमेरिकी शुल्क का खास असर नहीं

नई दिल्ली। भारतीय मोटर वाहन घटक विनिर्माता कंपनियां जिनकी विनिर्माण सुविधाएं कनाडा और मैक्सिको में हैं, उन पर अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिकी प्रशासन ने दोनों देशों को अतिरिक्त शुल्कों से छूट दी गई है। फेंटेनाइल और माइग्रेशन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत मौजूदा आदेश के कारण व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि बुधवार को घोषित नए शुल्क कनाडा और मैक्सिको पर लागू नहीं होंगे।

इसके परिणामस्वरूप अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के अनुरूप दोनों देशों की वस्तुओं पर शून्य शुल्क लगेगा, जबकि गैर-अनुपालन वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगेगा। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी भारतीय वाहन घटक विनिर्माता कंपनियां पहले ही कह चुकी हैं कि चूंकि उनके उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा यूएसएमसीए के अनुरूप है, इसलिए उन पर ट्रंप के आदेशों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रंप के 26 मार्च के आदेश के बाद पिछले महीने संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा था कि कंपनी और/या इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा अमेरिका में अपने विभिन्न ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो अमेरिका में निर्मित है या यूएसएमसीए के तहत आता हैइसलिए हमारे वर्तमान आकलन के अनुसार उक्त कार्यकारी आदेशों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।'' हालांकि, कंपनी ने स्वीकार किया कि वाहन घटकों सहित वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन हो सकते हैं। ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित शुल्क में वाहन व उसके घटक और स्टील तथा एल्युमीनियम की वस्तुएं शामिल नहीं हैं। इन पर 26 मार्च को घोषित आदेश के तहत पहले से ही 25 प्रतिशत शुल्क लगा हुआ है जो तीन अप्रैल की मध्यरात्रि से प्रभावी होंगे।

इस पर अन्य शुल्क तीन मई तक लागू किए जाने की आशंका है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का अमेरिका को वाहन घटकों का निर्यात 6.79 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि उसने 15 प्रतिशत आयात शुल्क पर अमेरिका से 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। अमेरिका को भारत से सबसे अधिक इंजन कंपोनेंट, पावर ट्रेन और ट्रांसमिशन का निर्यात किया जाता है।

हीरो मोटोकॉर्प की मार्च में बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की मार्च में कुल बिक्री सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 5,49,604 इकाई हो गई। कंपनी ने मार्च, 2024 में 4,90,415 वाहन बेचे थे। हीरो मोटोकॉर्प ने बयान में कहा कि घरेलू बाजार में उसकी थोक बिक्री मार्च में 5,10,086 इकाई रही जो मार्च, 2024 के 4,59,257 इकाई के आंकड़े से 11 प्रतिशत अधिक है। निर्यात सालाना आधार पर 31,158 इकाई से बढ़कर 39,518 इकाई हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कुल बिक्री 58,99,187 रही, जो 2023-24 में 56,21,455 इकाई रही थी। बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) श्रेणी में अपनी स्थिति का विस्तार करते हुए कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे अधिक ईवी बिक्री हासिल की, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में करीब 200 प्रतिशत बढ़ी।

सांसद महेश शर्मा ने लोकसभा में उठाया ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो लाने का मुद्दा

नई दिल्ली/नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंबे समय से लंबित मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्र के सांसद डॉ. महेश शर्मा ने लोकसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की शो विंडो बन चुका है। यहां बढ़ती आबादी और छात्रों की संख्या को देखते हुए मेट्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने सदन में कहा कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. एम. लोकेश से उन्हें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय में यह फाइल कई महीनों से लंबित है। उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान डॉ. महेश शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि नोएडा के कालिंदी कुंज से ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह हाईवे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बचाएगा और एयरपोर्ट तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेगा।सांसद ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में परिवहन की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहां आठ लाख से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, जिसमें बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय परिवार और छात्र शामिल हैं। शहर बसाते समय यहां मेट्रो विस्तार का वादा किया गया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बावजूद परियोजना शुरू नहीं हो पाई है। डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बनने जा रहा है।

ऐसे में 25 साल पुरानी एक्सप्रेसवे की स्थिति को सुधारना और उसे फिर से चालू करना बेहद जरूरी है, ताकि गाजियाबाद और अन्य आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। सांसद ने मेट्रो परियोजना और जेवर एयरपोर्ट से जुड़े सभी बुनियादी ढांचे के कार्यों को जल्द पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि यह क्षेत्र औद्योगिक और आर्थिक रूप से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

छात्राओं ने संस्कृत के श्लोक के द्वारा संस्कारों का महत्व समझाया

नोएडा। राजकीय डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राएं एक से बढ़कर एक कमाल कर रहे हैं। भारतीय जनमानस में मौजूद जीवन के प्रत्येक पक्ष को नोएडा के छात्र-छात्राएं बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं। नोएडा के राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता जीवन के हर पहलू को समझने में छात्र-छात्राओं को पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि नोएडा के राजकीय डिग्री कॉलेज की छात्राएं संस्कृत जैसी पुरातन भाषा में वेद मंत्रों का शानदार उच्चारण कर रही हैं।

नोएडा की राजकीय डिग्री कॉलेज में बृहस्पतिवार को बहुत ही अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल नोएडा के डिग्री कॉलेज में जीवन में संस्कारों का महत्व तथा प्रभाव विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं ने बड़े ही अनोखे अंदाज में संस्कृत के मुश्किल मंत्रों का आसानी से उच्चारण किया। इस पूरे कार्यक्रम के विषय में जानने से पहले आप यहां दी जा रही वीडियो में नोएडा के डिग्री कॉलेज की इस छात्रा को संस्कृत के मंत्र का उच्चारण करते हुए देख लीजिए यह नजारा देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नोएडा के डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी सोनी ने बताया कि बृहस्पतिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ) राजीव गुप्ता के मार्गदर्शन में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ नीतू अवस्थी द्वारा जीवन में संस्कारों का महत्व तथा प्रभाव विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर के माध्यम से संस्कारो के विषय में बताते हुए उसमें प्रयुक्त मंत्रों का सस्वर वाचन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उमा मिश्रा, द्वितीय स्थान रौनक राज ,तृतीय स्थान प्रिंसी शुक्ला व स्वाति ने प्राप्त किया। प्रोफेसर (डॉ) राजीव गुप्ता ने कार्यक्रम में राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। संस्कारों से आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास होता है तथा संस्कार से मानव में शिष्टाचार एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है।

कार्यक्रम में नंदिनी झा, रौनक,आंचल भाटी, प्रिंसी शुक्ला, उमा ,कीर्ति पांडे , स्वीटी ,लक्ष्मी, माला इत्यादि छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में डॉ शालिनी सोनी तथा डॉ ममता गौतम उपस्थित रही।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया जिनमें से एक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान फर्रुखाबाद निवासी निलेश चौहान और नोएडा के बहलोलपुर निवासी आदित्य कुमार के रूप में हुई है जो 50 से अधिक आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस टीम बहलोलपुर अंडरपास पर जांच कर रही थी तभी गढ़ी गोल चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने लगभग एक किलोमीटर दूर तक उनका पीछा किया। अवस्थी ने कहा कि खुद को घिरता देख एक बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली एक आरोपी के पैर में जा लगी। उन्होंने बताया कि दोनों के पास से एक तमंचा, चोरी किए आठ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

थैलेसीमिया मरीजों के लिए राहतः जीआईएमएस ग्रेनो में शुरू हुई मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इलाज की सुविधा

ग्रेटर नोएडा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीआईएमएस), ग्रेटर नोएडा ने राष्ट्रीय थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी, दिल्ली के सहयोग से 27 फरवरी 2025 से थैलेसीमिया मरीजों के लिए इलाज सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जांच और आयरन चेलेशन थेरेपी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। इस सेवा का उद्घाटन जीआईएमएस के निदेशक ब्रिगेडियर डॉ. राकेश के. गुप्ता और राष्ट्रीय थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी के डॉ. जे. एस. अरोड़ा ने किया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनता है। दुनिया भर में करीब 27 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। भारत में थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, जहां हर साल 10,000 से 15,000 नए मामले सामने आते हैं। इस बीमारी का एकमात्र स्थायी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) है, लेकिन यह प्रक्रिया महंगी और सभी मरीजों के लिए सुलभ नहीं होती। ऐसे में मरीजों को बार-बार रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की जरूरत होती है, जिससे शरीर में आयरन की अधिकता हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए आयरन चेलेशन थेरेपी आवश्यक होती है। ब्रिगेडियर डॉ. राकेश के. गुप्ता ने बताया कि जीआईएमएस में थैलेसीमिया मरीजों को निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नियमित जांच और आयरन चेलेशन थेरेपी दी जाएगी।

विशेषज्ञों की टीम करेगी इलाज

थैलेसीमिया मरीजों की देखभाल जीआईएमएस के पीडियाट्रिक्स विभाग की विशेषज्ञ टीम करेगी, जिसमें एचओडी डॉ. रुचिका भटनागर, डॉ. सुजया मुखोपाध्याय, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. मीतू सिंह और डॉ. संजू यादव शामिल हैं।

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर

थैलेसीमिया मरीजों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं: +91 94574 09011, +91 95823 42249

साथ ही, मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस पहल के तहत थैलेसीमिया रोग से जुड़ी जानकारी को बढ़ाने, प्रारंभिक जांच को बढ़ावा देने और मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।राष्ट्रीय थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी की स्थापना 1991 में हुई थी और यह थैलेसीमिया के रोकथाम और इलाज के लिए समर्पित संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और परिवारों व डॉक्टरों को इस बीमारी के नवीनतम उपचारों के प्रति जागरूक करना है।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश सौरव द्विवेदी ने बुधवार को इस मामले में सत्यवीर को दोषी ठहराया। प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 22 अक्टूबर 2020 को जेवर थाना क्षेत्र के एक गांव का है जब रात करीब आठ बजे पीड़िता पड़ोस के एक घर के पास लगे सरकारी नल से पानी लेने गई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोसी सत्यवीर ने नाबालिग को जबरन अपने घर के अंदर खींच लिया और उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी वहां से निकाल कर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई।

प्रवक्ता ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और वह कक्षा छह में पढ़ती थी। इस मामले में जेवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत में हुई जिसने गवाहों व पीड़िता के बयान दर्ज किये।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सतबीर को दोषी करार देते हुए बुधवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और यह धनराशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बीजेपी स्थापना दिवस पर बैठक, बूथ स्तर तक पहुंचेगा विकसित भारत अभियान

ग्रेटर नोएडा। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस (6 अप्रैल – 12 अप्रैल) को लेकर गौतमबुद्ध नगर जिला इकाई की बैठक गुरुवार को आशीर्वाद पैलेस, साकीपुर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर और क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स शामिल हुए।

बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री दीपक भारद्वाज ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए हरीश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल भारत के लिए विकास और परिवर्तन का नया युग लेकर आया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा का 45वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाने की योजना बनाई गई है। बैठक में क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स ने कहा कि पार्टी ने

गौतमबुद्ध नगर को ऊर्जावान जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में जिला महामंत्री दीपक भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष मनोज गर्ग, देवा भाटी, वीरेन्द्र भाटी, मीडिया प्रभारी कर्मवीर आर्य, राज नागर, रजनी तोमर, जितेंद्र भाटी, बिमल पुंडीर, सत्यपाल शर्मा, अनीता गौतम, गुरुदेव भाटी, पंकज रावल, इन्द्र नागर, अजय निगम, पवन त्यागी, अर्पित तिवारी, सचिन शर्मा, मनोज प्रधान, इन्द्रजीत टाइगर, दिनेश भाटी, राज सिंह प्रधान, संजय भाटी, रवि जिंदल, अरुण प्रधान, विजय रावल, अशोक रावल, श्यामवीर भाटी, हरिदत्त शर्मा, महेंद्र नागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि स्थापना दिवस से लेकर अंबेडकर जयंती तक सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

समारोह की प्रमुख रूपरेखा

- 6 अप्रैल से सभी बूथों पर भाजपा का ध्वज लगाया जाएगा, कार्यकर्ता #BJPForViksitBharat हैशटैग के साथ सेल्फी पोस्ट करेंगे।
- 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।
- 7 से 12 अप्रैल तक 'गांव चलो अभियान' के तहत कार्यकर्ता प्रवास करेंगे।
- 8 और 9 अप्रैल को सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित होंगे।
- 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।

दुकान से नगदी और कीमती सामान चोरी

नोएडा। सेक्टर-नौ स्थित स्टील फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन बनाने वाली दुकान में रखी नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। मौके पर पहुंची थाना फेज-वन पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस दुकान के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मामले की जांच कर रही है।

सिंह स्टील के मालिक रविंद्र ने गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना दी कि जब वह अपनी दुकान खोलने के लिए आए तो सामान तितर बितर पड़ा था। अज्ञात बदमाशों ने उनकी दुकान के अंदर घुसकर वहां रखे 80 हजार रुपये और अन्य सामान चोरी कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दुकान के पास लगे एक पेड़ के सहारे बदमाश दुकान की छत पर पहुंचे तथा छत के रास्ते दुकान के अंदर घुसे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे तथा आसपास के दुकानों पर लगे कैमरों की सहायता से बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस को संदेह है कि इस घटना के पीछे दुकान में काम करने वाले किसी कर्मचारी का हाथ भी हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है।

सरकारी अस्पताल में नवरात्रि के दौरान जन्म लेने वाली कन्याओं और उनकी माताओं को उपहार देकर उनका सम्मान किया

नोएडा। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान नोएडा शहर में एक शानदार मिसाल पेश की गई है। नोएडा के एक प्रमुख सामाजिक संगठन ने नवरात्रि के दौरान गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली नवजात कन्याओं का कुछ अलग ढंग से पूजन किया है। नोएडा के सरकारी अस्पताल में नवरात्रि के दौरान जन्म लेने वाली नवजात कन्याओं तथा उनकी माताओं को उपहार देकर उनका सम्मान किया गया। नोएडा के सरकारी अस्पताल के प्रशासन तथा नवजात कन्याओं के परिवारों ने इस पहल का स्वागत करते हुए खूब सराहना की है।

सब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के महत्व को देखते हुए नोएडा में सक्रिय सामाजिक संगठन लायंस क्लब नोएडा एलीट ने शानदार उदाहरण पेश किया है। ज्यादातर लोग नवरात्रि के पर्व के पूरा होने पर अष्टमी अथवा नवमी को कन्या पूजन करते हैं। लायंस क्लब नोएडा एलीट ने नवरात्रि के बीच में ही चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर बृहस्पतिवार को 'कन्या पूजन' किया। लायंस क्लब नोएडा एलीट की सचिव पूनम शर्मा ने चेतना मंच को बताया कि बृहस्पतिवार को लायंस क्लब नौएडा एलीट के द्वारा नवरात्रि पर्व के उपलक्ष में "नवजात कन्या शिशुओ एवं उनकी माताओ" (जच्चा एवं बच्चा) को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस सेवा कार्य में एक किट जिसमें नवजात बच्चियो के लिए 2 जोडे कपड़े, खिलौने, साबुन, पाउडर व तेल, कम्बल, मचछरदानी दी गई एव मां के लिए देसी घी, अजवाइन, जीरा आदि समान दिया गया।

इस अवसर पर जिला सरकारी अस्पताल की डा. रेणु अग्रवाल (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक), डा. नरेंद्र कुमार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) भी उपस्थित रहे एवं जिला 321C1 के उपमंडलाध्यक्ष लायन विनय सिसौदिया एवं लायन शशि सिसौदिया व रीना शर्मा, लायन पिंकी गुप्ता, लायन निशि अग्रवाल, लायन राजेश मेहदिरत्ता,जोन चेयरपर्सेन लायन संजीव शर्मा, पूनम शर्मा (सचिव), मोना चावला (कोषाध्यक्ष), लायन कुशल वार्ष्णेय, लियो भावना मेहदिरत्ता, लिओ सिमरन मेहदिरत्ता आदि सदस्यो ने उपस्थित होकर सेवा कार्य में हाथ बटाया। लायंस क्लब नौएडा एलीट के सेवाकार्य के लिए सभी उपस्थित सम्मानित लॉयन सदस्यों को धन्यवाद देकर भविष्य में भी सेवा कार्यो मे सहयोग का आश्वासन डाक्टर नरेंद्र कुमार ने दिया।

अर्जुन, युवराज गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार

ग्रेटर नोएडा। दिल्ली के अर्जुन प्रसाद और चंडीगढ़ के युवराज संधू बृहस्पतिवार को यहां तीसरे दौर में तीन अंडर 69 के समान स्कोर के साथ अडानी आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार हैं। अर्जुन और युवराज का कुल स्कोर 10 अंडर 206 है और उन्होंने शीर्ष पर दो शॉट की बढ़त बना रखी है। ग्रेटर नोएडा के सपतक तलवार ने भी तीसरे दौर में 69 का स्कोर बनाया और वह दो स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनका कुल स्कोर आठ अंडर 208 है। दिल्ली के हनी बैसोया और चंडीगढ़ के हरेंद्र गुप्ता तीसरे दौर में 72 के समान स्कोर से कुल छह अंडर 210 के स्कोर से संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

ईएसवीसी-3000 का भव्य समापन, सौलर और इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक ने किया मंत्रमुग्ध

ग्रेटर नोएडा। गलगोटियास यूनिवर्सिटी में आयोजित 10वें इलेक्ट्रिक सोलर व्हीकल चैंपियनशिप-3000 का भव्य समापन हुआ। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक चले इस प्रतिष्ठित आयोजन में आईएसआईई इंडिया (इम्पीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर्स, इंडिया) के सहयोग से देशभर के युवा इंजीनियरों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा और नवाचार का प्रदर्शन किया।

भारत की शीर्ष सौर वाहन प्रतियोगिताओं में शामिल ईएसवीसी-3000 में इस बार दो प्रमुख श्रेणियां थीं– एसआईईपी ई-बाइक चैलेंज (सीजन-5) और ईएसवीसी-3000 सोलर व्हीकल चैंपियनशिप। इस दौरान प्रतिभागियों ने वाहन निर्माण, दक्षता, सहनशक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 20 टीमों ने सख्त तकनीकी निरीक्षण (टीआई) पास किया, जिसमें वाहन की सुरक्षा, यांत्रिक मजबूती और विद्युत प्रणाली की जांच की गई। इसके बाद विभिन्न परीक्षणों में 20 टीमों ने

ब्रेकिंग टेस्ट, 19 ने एक्सेलेरेशन टेस्ट, 4 ने ब्रेकिंग, 2 ने एक्सेलेरेशन और 2 टीमों ने हिल क्लाइंबिंग टेस्ट में सफलता हासिल की। इस आयोजन को और रोमांचक बनाने के लिए रेड बुल वाहन प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने छात्रों और दर्शकों को ग्रीन एनर्जी इनोवेशन के प्रति प्रेरित किया। 31 मार्च को आयोजित ई-बाइक चैलेंज (सीजन-5) की 45 मिनट की एंड्यूरेंस रेस ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता में टीम एमवी-ट्रॉनिक्स ने चैंपियनशिप का खिताब जीता, जबकि टीम फाल्कन रेसर्स और टीम डार्क ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर-अप का स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, बेस्ट ऑफ-रोड, बेस्ट हिल क्लाइंब, बेस्ट एक्सेलेरेशन और बेस्ट इनोवेशन जैसी विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार वितरित किए गए। 1 अप्रैल को हुए ईएसवीसी-3000 सोलर व्हीकल चैंपियनशिप के फाइनल में देशभर की टीमों ने अपने सौर ऊर्जा संचालित वाहनों की दक्षता और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने इनोवेटिव डिजाइन और ऊर्जा-कुशल तकनीकों का बेहतरीन उपयोग कर प्रतियोगिता को बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बना दिया।गलगोटियास यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने इस आयोजन को विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि ईएसवीसी-3000 केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह हरित और सतत भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह देखना बेहद प्रेरणादायक है कि युवा इंजीनियर नवाचार कर रहे हैं और स्वच्छ गतिशीलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।

गौरतलब है कि 2017 से गलगोटियास यूनिवर्सिटी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की आधिकारिक मेजबान रही है। इस वर्ष भी इस आयोजन को एनबीसी बेयरिंग्स (सीके बिड़ला ग्रुप) और ईएस जैसे प्रमुख प्रायोजकों का समर्थन प्राप्त था। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को उनकी असाधारण तकनीकी क्षमताओं और नवीकरणीय ऊर्जा परिवहन में योगदान के लिए बधाई दी। ईएसवीसी-3000 का यह सफल संस्करण विश्वविद्यालय की तकनीकी नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म 'राहु केतु' में काम करने के लिये उत्साहित है

शालिनी पांडे

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शालिनी पांडे फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म 'राहु केतु' में काम करने के लिये उत्साहित है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और शानदार अदाकारी के लिए मशहूर शालिनी पांडे इस साल फिल्म डब्बा कार्टेल में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को पहले ही प्रभावित कर चुकी हैं। अब वह बड़े पर्दे पर अपनी कशिश बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शालिनी, जी स्टूडियोज़ के बैनर तले बन रही फैंटेसी-कॉमेडी 'राहु केतु' में नजर आएंगी। विपुल विग द्वारा निर्देशित यह फिल्म हास्य और फैंटेसी का अनोखा मिश्रण लेकर आ रही है। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा के साथ स्क्रीन साझा करते हुए, शालिनी इस फिल्म में मजेदार और रोमांचक किरदार में नजर आएंगी, जो उनकी फिल्मोग्राफी में एक नया आयाम जोड़ेगा। फिल्म की शूटिंग की आधिकारिक शुरुआत मुहूर्त पूजा के साथ हो गयी है। शालिनी पांडे ने कहा,जब हास्य, फैंटेसी और थोड़ा सा खगोलीय रोमांच एक साथ मिल जाए, तो यह किसी जादू से कम नहीं होता! 'राहु केतु' ऐसी ही एक फिल्म है, जो इन सभी तत्वों को एक साथ लेकर आ रही है और इस शानदार टीम के साथ इसका हिस्सा बनकर मैं बेहद उत्साहित हूं। अब बस इंतजार है कि आप सब इस पागलपन का अनुभव करें, जिसे हम बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं।

अपूर्वा अरोड़ा

ने वेवसीरीज फैमिली आज कल के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा ने वेबसीरीज फैमिली आज कल के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया है। अपूर्वा अरोड़ा जश्न के मूड में हैं क्योंकि उनकी वेब सीरीज़ फैमिली आज कल ने सफलता के एक साल पूरे कर लिए हैं। इस शो ने प्यार, ड्रामा और हास्य के मिश्रण के साथ आधुनिक पारिवारिक गतिशीलता को खूबसूरती से दर्शाया, जिसे दर्शकों से बहुत सराहना मिली। सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अपूर्वा ने इस यात्रा पर विचार किया और इस मील के पत्थर के बारे में अपनी खुशी साझा की। शो के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, अपूर्वा ने कहा, यह अविश्वसनीय है कि एक साल हो गया है ! फैमिली आज कल मेरे लिए सिर्फ़ एक शो से कहीं बढ़कर है ।यह भावनाओं, हंसी और अविश्वसनीय यादों से भरा एक अनुभव है। दर्शकों से मिले प्यार और समर्थन ने मुझे अभिभूत कर दिया है, और मैं ऐसी चीज़ का हिस्सा बनने के लिए आभारी हूँ जो इतने सारे लोगों के दिलों को छूती है। शो की पहली वर्षगांठ पर, अपूर्वा ने पूरी टीम और प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ₹यह शो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। इस यात्रा के दौरान हमें प्यार और समर्थन देने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी कई मील के पत्थर हैं।

स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा के दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा : कंवर ढिल्लों

मुंबई। अभिनेता कंवर ढिल्लों का कहना है कि स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। स्टार प्लस के शो 'उड़ने की आशा' के नये प्रोमो ने फैंस को पूरी तरह से चौंका दिया है! जब दर्शकों को लगने लगा था कि सचिन और साइली की कहानी अब समझ आ रही है, तभी देशमुख परिवार की अचानक आई अमीरी ने सबकुछ उलटा-पुलटा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पल में उनकी किस्मत बदल गई, जो परिवार अब तक पैसों की तंगी से जूझ रहा था, वो अचानक शाही अंदाज में एंट्री कैसे ले रहा है।ये बदलाव सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रहा है। उनके इस अचानक से अमीर बनने के पीछे का राज़ क्या है। शो में सचिन का किरदार निभा रहे कन्वर ढिल्लों आने वाले एपिसोड्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा,दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा।पूरे शो में लोग यह सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन यह पूरा सीन पागलपन से भरपूर होने वाला है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि दर्शक ये एपिसोड्स देखें।

सर्दियों में सेहत का सस्ता खजाना, रहें महफूज

अदरक सिर्फ एक मसाला नहीं है। सेहत के लिए वरदान है। चाय में डाल कर पिएं, काढ़ा बनाएं या सब्जी में मसाले की तरह इस्तेमाल करें। इसमें भरपूर आयोडीन, कैल्शियम व विटामिन होते हैं। सूजन व दर्दकम करने के गुण होते हैं। यह शक्तिशाली एंटी वायरल भी है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। ' पेट की समस्याओं में लाभकारी होता है। गरिष्ठ भोजन खाने से होने वाला अपच दूर होता है और पाचन में सुधार होता है। अदरक के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है व रक्तसंचार ठीक रहता है। अदरक संक्रमण से बचाता है। अदरक में एंटी फंगल और कैंसर प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं। गठिया, सियाटिका, आश्राइटिस गर्दन व रीढ़ की हड्डी के रोगों में इसका काढ़ा फायदा पहुंचाता है।

गजब है गाजर-

गाजर में बीटा-कैरोटीन भरपूर होता है, जिसे शरीर विटामिन-ए में बदल लेता है। गाजर को सलाद के रूप में खाएं या इसकी सब्जी बना कर, यह फायदेमंद होता है। दाम में कम और पोषक तत्वों का भंडार होने की वजह से इसे सुपरफूड कहा जाता है। टमाटर और चुकन्दर मिला कर इसका जूस पीना त्वचा के साथ आंखों के लिए फायदेमंद रहता है। गाजर में मौजूद विटामिन-ए शरीर को संक्रमण से दूर रखता है। सांस से जुड़े रोगों में फायदा होता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग तत्व असमय बुढ़ापा आने से रोकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन-सी और के, पोटैशियम व आयरन खांसी-जुकाम से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर अधिक होता है, जो पाचन सही रखता है

हरी पत्तेदार सब्जियां-

सर्दियां सरसों के साग के अलावा पालक, मेथी, बथुआ, सोया और पत्तागोभी के स्वाद लेने का मौसम है। इनमें कैलरी न के बराबर होती है और पोषक तत्व प्रचुरता में होते हैं। सेहत और स्वाद दोनों की दृष्टि से लाजवाब होती हैं पत्तेदार सब्जियां। पालक सीमित मात्र में ही खाना चाहिए। इसमें भरपूर आयरन होता है, पर ज्यादा आयरन सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिन्हें खून की कमी है, उन्हें सप्ताह में दो बार पालक जरूर खाना चाहिए। पकाते समय पालक के डंठल भी इस्तेमाल करने चाहिए। ब्रोकली में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम व मैग्नीशियम प्रचुरता में होते हैं। इसके सेवन से लो ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है। सरसों और मेथी में भरपूर कैल्शियम होता है। सरसों में फोलेट और विटामिन ईभी पर्याप्त मात्र में होता है। यह हड्डियों को मजबूत बना कर गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। यह अस्थमा, दिल के रोगों व मीनोपॉज में भी फायदा पहुंचाता है।

गुणकारी गुड़-

तासीर में गर्म गुड़ को सर्दियों की मिठाई भी कह सकते हैं। सेहत और त्वचा दोनों के लिए यह फायदेमंद है। यह खून भी साफ करता है। मेटाबॉलिज्म धीमा नहीं पड़ने देता। गुड़ में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और कुछ मात्र में कॉपर भी पाया जाता है। चीनी की तुलना में इसमें पचास गुना ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। मीठा होने के बावजूद यह वजन को नियंत्रित रखने में लाभकारी है। गुड़ शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है। यह भूख के साथ-साथ खून भी बढ़ाता है। गुड़ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती और स्मरण शक्ति तेज होती है। गर्म दूध के साथ इसका सेवन वजन को नियंत्रित रखने में बहुत मदद करता है।

सेहत से भरपूर खजूर-

सर्दियों में नियमित खजूर का सेवन न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। खजूर सुपाच्य होता है और इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्र में होता है। इसमें वसा ना के बराबर होती है, इसलिए वजन बढ़ने की भी चिंता नहीं रहती। रोजाना दो से तीन खजूर हमारी फाइबर की रोजाना की छह प्रतिशत जरूरत को पूरा कर देते हैं। यह रक्त में हीमोग्लोबिन का सही स्तर बनाए रखता है। खजूर में विटामिन (ए, बी, के) के अलावा पोटैशियम और मैग्नीशियम प्रचुरता में होते हैं। खजूर दिल को दुरुस्त रखता है, बल्कि प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और पेनक्रियाज के कैंसर से भी बचाव में सहायक है।

बलशाली बाजरा-

बाजरा बढ़ते बच्चों और बुजुर्गो के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्र में पाया जाता है। कुछ लोग इसे गरीबों का अनाज या मोटा अनाज भी कहते हैं। गांव-देहात में खाया जाने वाला बाजरा अपने कमाल के गुणों के कारण आज सुपरफूड के रूप में पहचाना जाने लगा है। इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर भारी मात्र में पाए जाते हैं। बाजरे की रोटी पचने में बहुत आसान होती है और इसमें ग्लूटन नहीं होता, इसलिए जिन लोगों को गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, उनके लिए बाजरे की रोटी बहुत लाभकारी होती है। शुगर के मरीजों को भी बाजरा खाने की सलाह दी जाती है। किडनी में पथरी होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बाजरे में प्रचुर मात्र में फाइबर होता है। यह कब्ज, गैस और अपच से छुटकारा दिलाता और पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है। गेहूं और चावल की अपेक्षा बाजरे में कई गुना ज्यादा एनर्जी होती है और घी, धनिए व पुदीने की चटनी के साथ खाने से इसकी पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

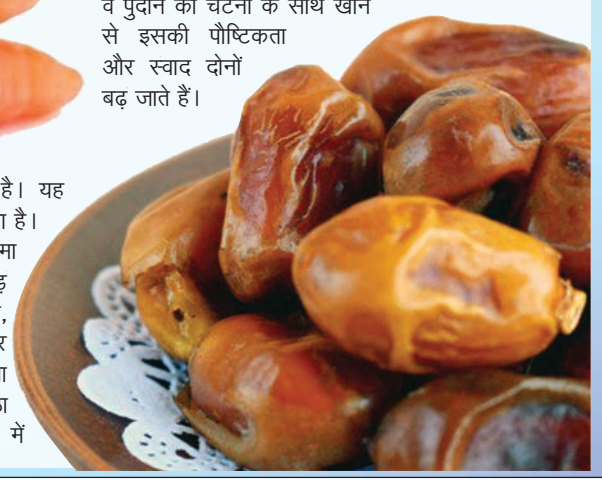

गेंदा फूल का वानस्पतिक नाम

गेंदा को अंग्रेजी में मेरी गोल्ड भी कहते हैं, जो प्रभु जीसस की मां मरियम के नाम पर रखा गया है। इसे हजारा के नाम से भी जाना जाता है। गेंदा के फूल को गरीबों का केसर भी कहा जाता है। गेंदे के फूल में विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गेंदा के फूल में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाने के कारण यह शरीर को कैंसर से लड़ने की शक्ति देता है। इसके लिए गेंदा के फूल या तना या सम्पूर्ण पौधा का काढ़ा बनाकर सुबह शाम नियमित सेवन करने से कैंसर में लाभ होता है। गेंदा के फूल का काढ़ा बनाकर रात्रि भोजन के बाद सोने से पहले लेने पर ट्यूमर जड़ से नष्ट हो जाता है। गेंदा का फूल बुखार को भी समाप्त करता है, चुकीं इसके फूल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, अतः इसके फूल की चाय बनाकर पीने से बुखार के सभी लक्षण ठीक हो जाते हैं। गेंदा का फूल योनि संक्रमण को भी दूर करता है, इसके लिए गेंदे के फूल की पंखुड़ी का काढ़ा बनाकर इस पानी को स्नान के पानी में मिलाकर लगातार दो सप्ताह तक स्नान करने से योनि संक्रमण समाप्त हो जाता है। गेंदा का फूल नपुंसकता को भी दूर करता है, इसके लिए इसके फूलों को सुखाकर इसके बीज में मिश्री मिलाकर नित्य सेवन करने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है,तथा पुरुष वीर्य वर्धक हो जाता है। गेंदा का फूल श्वेत प्रदर(ल्यूको रिया) में भी लाभकारी होता है, इसके लिए गेंदा के फूल का रस पांच से दस ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लुकोरिया में लाभ होता है। गेंदा के फूलों के सेवन से पथरी को भी नष्ट किया जा सकता है,इसके लिए गेंदा के बीस से तीस ग्राम पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन करने से पथरी गलकर निकल जाती है। गेंदा फूल के सेवन से बवासीर रोगियों को भी लाभ होता है,इसके लिए दस ग्राम गेंदा के पत्तो में दो ग्राम काली मिर्च पीसकर पिलाने से बवासीर में काफी लाभ होता है, या फिर इसके पत्तों को पीसकर मस्सों पर लेप करने से भी फायदा होता है। गेंदा के फूल का सेवन सभी प्रकार के नेत्र रोग में लाभकारी होता है, इसके लिए गेंदा फूल की चाय का सेवन या फिर गेंदा फूल के रस से आंखो को धोया जा सकता है। त्वचा में जलन या सूजन होने पर इसके फूलों को पीसकर लेप लगाने से त्वचा संबंधी सभी विकारों का नाश होता है। गेंदा के इस्तेमाल से स्तन में होने वाले गांठ को भी ठीक किया जा सकता है, इसके लिए गेंदा के पत्तों को पीसकर स्तनों पर लगाने से गांठें बिखर जाती हैं, तथा सूजन ठीक हो जाता है। गेंदा का फूल श्वसन रोग से भी मुक्ति देने में कारगर होता है,इसके लिए इसके बीजों का चूर्ण दो से पांच ग्राम,दस ग्राम गुड़ और एक चमच दही के साथ दिन में तीन बार सेवन किया जाए तो श्वसन संबंधी सभी रोगों के साथ साथ दमा और खांसी भी दूर हो जाते । गेंदा के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने पर दांत के दर्द में शीघ्र आराम मिलता है,साथ ही मूह की दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है।

आज का राशिफल

मेष राशि :-मन प्रसन्न रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा।

वृषभ राशि :-आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परन्तु मन चिंतित हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

मिथुन राशि :-व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के साधन बन सकते हैं।

कर्क राशि :- आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

सिंह राशि :-मन प्रसन्न रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। परिवार का साथ रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

कन्या राशि :-आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

तुला राशि :- पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है।

वृश्चिक राशि :-वाणी में मधुरता रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशि :- मन में शान्ति एवं प्रसन्नता रहेगी। सन्तान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सद्भाव का माहौल रहेगा।

मकर राशि:-कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। धर्म-कर्म में व्यस्तता रहेगी।

कुम्भ राशि :- आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं।

मीन राशि :- पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी।

-ज्योतिषाचार्य: पंडित जितेंद्र तिवारी

मुंबई और लखनऊ के बीच मैच में रोहित और पंत पर रहेगी निगाह

लखनऊ। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में शुक्रवार को यहां जब आमने सामने होंगी तो सभी की निगाह रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का इस सत्र में अभी तक प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तथा तीन मैच में उसके केवल दो अंक हैं। भारतीय कप्तान रोहित की खराब फॉर्म मुंबई के लिए चिंता का विषय है। यही बात लखनऊ के कप्तान पंत पर भी लागू होती है जो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का असर परिणाम पर साफ नजर आ रहा है। इन दोनों टीमों ने अभी तक तीन में से केवल एक मैच जीता है और ऐसे में शुक्रवार को होने वाले मैच में जो टीम परिस्थितियों से बेहतर सामंजस्य बिठाएगी, उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। यही नहीं इस बार क्यूरेटर घरेलू टीमों के अनुकूल पिच तैयार नहीं कर रहे हैं जिस पर कुछ फ्रेंचाइजी के कोच और खिलाड़ियों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम की जीत की संभावना बढ़ जाएगी।

मुंबई के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट भी चिंता का विषय है। बुमराह कब तक वापसी करेंगे इसको लेकर हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम ने चुप्पी साध रखी है। बुमराह की जगह लेना आसान नहीं है लेकिन बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अश्वनी कुमार ने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके मुंबई की टीम में आशा की नई किरण जगाई है। अश्वनी कुमार ने इस मैच में 24 रन देकर चार विकेट लिए थे। पंजाब के रहने वाले इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में केवल चार टी20 मैच खेलने के बाद मुंबई की तरफ से आईपीएल में पदार्पण करते हुए शानदार प्रदर्शन किया तथा अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को आउट किया। मुंबई के गेंदबाजों ने कोलकाता के खिलाफ वानखेड़े में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेलटन थे जिन्होंने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

मुंबई को अगर इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखना है तो फिर रोहित और सूर्यकुमार यादव को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। जहां तक लखनऊ की बात है तो विशाखापत्तनम में आईपीएल के शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल्स से मिली एक विकेट की निराशाजनक हार के बाद उसकी टीम अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लखनऊ के लिए अच्छी बात यह है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरण अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने तीन मैच में अभी तक 189 रन बनाए हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श को छोड़कर लखनऊ का कोई भी अन्य बल्लेबाज पूरण की तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। लखनऊ की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी और कप्तान पंत का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना है। लखनऊ के कुछ तेज गेंदबाज चोटिल हैं और ऐसे में उसके गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई संभाल रहे हैं। जहां तक पंत की बात है तो उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला और मैच अभ्यास की कमी का असर उनकी बल्लेबाजी में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यह आक्रामक बल्लेबाज अभी तक तीन मैच में केवल 17 रन बना पाया है।

इस प्रकार हैं दोनों टीम

लखनऊ सुपर जाइंट्सः ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल समद, आकाश दीप, आकाश सिंह, अवेश खान, आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, हिम्मत सिंह, शमर जोसेफ, आर्यन जुयाल, अर्शिन कुलकर्णी, एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, डेविड मिलर, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, शाहबाज़ अहमद, मणिमारन सिद्धार्थ, शार्दुल ठाकुर, मयंक यादव।

मुंबई इंडियंसः हार्दिक पंड्या (कप्तान), अश्वनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमरा, दीपक चाहर, विल जैक्स, बेवॉन जैकब्स, रॉबिन मिंज, मुजीब उर रहमान, नमन धीर, विग्नेश पुथुर, सत्यनारायण राजू, रयान रिकेलटन, मिशेल सेंटनर, कर्ण शर्मा, रोहित शर्मा, कृष्णन श्रीजीत, अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, रीस टॉपले, सूर्यकुमार यादव।

विश्व मुक्केबाजी कपः मनीष राठौड, हितेश और अभिनाश ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली। भारत के मनीष राठौड़, हितेश और अभिनाश जामवाल ने बुधवार को अपने-अपने वजन वर्ग में आसान जीत के साथ विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में सेमीफाइनल में जगह बनाई।

जामवाल ने 65 किग्रा वर्ग में जर्मनी के डेनिस ब्रिल को सर्वसम्मत फैसले से हराया जबकि हितेश ने इटली के गैब्रिएल गुइडी रोनतानी को 70 किग्रा वर्ग में सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त दी। मनीष ने 55 किग्रा वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के पेरिस ओलंपियन यूसुफ चोटिया को हराया। दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन अंत में भारतीय मुक्केबाज विजयी रहा। तीन जज ने मनीष के पक्ष में फैसला दिया जबकि दो ने दोनों मुक्केबाजों को बराबर अंक दिए।

सेमीफाइनल में मनीष की भिड़ंत कजाखस्तान के नूरसुल्तान अल्तिनबेक से होगी जबकि हितेश को माकन तराओरे के खिलाफ खेलना है। जामवाल का सामना इटली के जियानलुइगी मलांगा से होगा।

बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड में होगा खिताबी मुकाबला

मैड्रिड। बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 1-0 से हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी रियाल मैड्रिड से होगा। बार्सिलोना की तरफ से फेरान टोरेस ने पहले हाफ में गोल किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच फरवरी में खेला गया सेमीफाइनल का पहला चरण 4-4 से बराबर रहा था। इस तरह से बार्सिलोना ने कुल मिलाकर 5-4 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। यह पिछले चार सत्र में पहला अवसर है जबकि बार्सिलोना इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। रियाल मैड्रिड ने मंगलवार को अतिरिक्त समय तक चले मैच में रियाल सोसिदाद को 5-4 के कुल स्कोर से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। इन दोनों टीमों के बीच 2013-14 सत्र के बाद पहली बार फाइनल खेला जाएगा। तब रियाल मैड्रिड ने खिताब जीता था।

सूर्यकुमार यादव मुंबई को छोड़कर कहीं नहीं जा रहाः मुंबई क्रिकेट संघ

मुंबई। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन किया कि सूर्यकुमार यादव अपने कुछ साथियों के साथ आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए गोवा जाने की योजना बना रहे हैं। एमसीए ने कहा कि भारत का टी20 कप्तान खेल के प्रत्येक प्रारूप में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रणजी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ कथित मतभेदों के कारण पहले ही मुंबई से गोवा जाने की घोषणा कर चुके हैं।

जायसवाल हालांकि तभी गोवा की टीम से जुड़ पाएंगे जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अपनी अंतर-राज्य स्थानांतरण विंडो खोलेगा। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सूर्यकुमार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई रणजी टीम छोड़ सकते हैं। असल में सूर्यकुमार ने खुद ही अपने एक्स हैंडल पर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। एमसीए सचिव अभय हदाप ने एक बयान में कहा कि मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को सूर्यकुमार यादव के कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ गोवा की टीम से जुड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की जानकारी है। उन्होंने कहा, कि एमसीए के अधिकारियों ने आज सुबह सूर्य से बात की और हम पुष्टि कर सकते हैं कि ये अफवाहें पूरी तरह से निराधार और झूठी हैं। सूर्यकुमार यादव मुंबई की तरफ से खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह मुंबई का प्रतिनिधित्व करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। एमसीए के सचिव ने कहा कि हम सभी से गलत सूचना फैलाने से बचने और हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने का आग्रह करते हैं।

इस बात की भी पुष्टि की जा सकती है कि हैदराबाद के लिए खेलने वाले तिलक वर्मा के गोवा में जाने की खबरें गलत पाई गई हैं।

दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों का सह आयोजक है भारत, योग और शतरंज में करेगा अगुवाई

संयुक्त राष्ट्र। भारत खेलों के माध्यम से कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों का सह आयोजक है जिसमें वह योग और शतरंज जैसे खेलों में अगुवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। सह आयोजक के रूप में, भारत शतरंज और योग में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

हरीश ने कह कि संयुक्त राष्ट्र खेल एकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना का उत्सव हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगली बार इन खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय टीम को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र खेल अप्रैल-मई 2025 में आयोजित किए जाएंगे। योग नौ अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नॉर्थ लॉन के रोज गार्डन में, जबकि शतरंज भी उसी दिन नॉर्थ लॉन के ओलंपिक कॉर्नर में आयोजित किया जाएगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून, 2023 को नौवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल नॉर्थ लॉन में एक ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किया था। हरीश ने कहा कि हालांकि हर कोई सक्रिय खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन राजनयिक समुदाय के अधिकतर सदस्य उत्साही प्रशंसक हैं। लोग अलग-अलग टीमों के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन खेल उन्हें एकजुट करते हैं।

उन्होंने कहा कि एक अरब से अधिक भारतीयों की तरह वह भी क्रिकेट प्रेमी हैं और उम्मीद जताई के अगली बार संयुक्त राष्ट्र खेलों में क्रिकेट भी शामिल होगा। हरीश ने कहा कि योग और शतरंज में आगे बढ़ना भारत के लिए सौभाग्य की बात है, जैसा कि पिछले साल हुआ था। उन्होंने कहा कि 2014 में रिकॉर्ड संख्या में सदस्य देशों के सह-प्रायोजन के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने के बाद से, योग दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जीवन का एक तरीका बन गया है।

हरीश ने कहा कि जहां तक शतरंज का सवाल है तो भारत ने सदियों पहले इस खेल को अपना दिया था। वर्तमान समय में शतरंज की दुनिया में भारत के युवा खिलाड़ियों का दबदबा है जो रिकॉर्ड तोड़कर और वैश्विक चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। भारतीय दूत ने विश्वास जताया कि मित्रता और सौहार्द की भावना क्षेत्र के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए पेशेवर और कार्यात्मक आचरण में भी दिखाई देगी।

संयुक्त राष्ट्र खेल सितंबर 2024 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र खेल और खेल के माध्यम से शांति और बेहतर दुनिया को बढ़ावा देने वाले अन्य प्रस्तावों पर आधारित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उद्घाटन संस्करण की तरह संयुक्त राष्ट्र खेल 2025 खेलों के माध्यम से सौहार्द, कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र खेल 2025 का उद्घाटन समारोह बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। इन खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, पिकलबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योग, शतरंज और दौड़ शामिल हैं। तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र खेल आयोजन समिति का अध्यक्ष है।

फीफा फुटबॉल रैंकिंगः भारत 127वें स्थान पर पहुंचा

नई दिल्ली। वैश्विक फुटबॉल नियामक संस्था फीफा की ओर से गुरुवार को जारी नवीनतम पुरुष रैंकिंग में भारत एक स्थान फिसलकर 127वें स्थान पर आ गया है। मार्च 2025 में एएफसी एशियाई कप क्वालीफाइंग मैच में ब्लू टाइगर्स को बांग्लादेश से ड्रॉ पर रोका गया था। इस परिणाम से बांग्लादेश को दो पायदान ऊपर चढ़कर 183वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। मिस्र की राष्ट्रीय टीम पिछली रैंकिंग में 33वें स्थान पर रहने के बाद विश्व स्तर पर 32वें स्थान पर पहुंच गई। मोरक्को विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर और सेनेगल विश्व स्तर पर 18वें स्थान पर है, जबकि अल्जीरिया अफ्रीका में चौथे और विश्व स्तर पर 36वें स्थान पर है और नाइजीरिया अफ्रीका में पांचवें और विश्व स्तर पर 43वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर अर्जेंटीना ने अपनी बढ़त बनाए रखी, जबकि स्पेन दूसरे स्थान पर पहुंच गया और फ्रांस तीसरे स्थान पर खिसक गया।

एएफआई ने फेड कप से पहले एथलीटों के लिए कम से कम एक प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य किया

नई दिल्ली। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 2025 सत्र की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप फेडरेशन कप में भाग लेने के लिए एथलीटों के लिए कम से कम एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता या ग्रां प्री जैसी देशव्यापी एकदिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि एथलीट पूरी तैयारी के साथ आएं या उनके प्रदर्शन में निरंतरता हो क्योंकि 27-31 मई तक कोरिया में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन फेडरेशन कप में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा जिसका आयोजन 21-24 अप्रैल तक केरल के कोच्चि में किया जाएगा। हालांकि एएफआई द्वारा प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए दोहरे ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों को इस नियम से छूट दी जाएगी।

एएफआई ने एक सर्कुलर में कहा कि इस प्रतियोगिता (फेडरेशन कप) में भाग लेने के लिए एथलीटों को वर्ष 2025 में एएफआई द्वारा स्वयं आयोजित की जानी वाली प्रतियोगिताओं के क्वालीफिकेशन प्रवेश मानकों को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा, कि एथलीटों के लिए 2025 में कम से कम एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता (पंजाब, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु में इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट) या चौथे इंडियन ओपन थ्रो/चौथे इंडियन ओपन जंप/छठे इंडियन ओपन 400 मीटर/इंडियन ग्रां प्री में भाग लेना अनिवार्य है। सर्कुलर के अनुसार, "कृपया ध्यान दें कि केवल 2025 के प्रदर्शनों पर ही विचार किया जाएगा और कोई भी पुराना प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि फेडरेशन कप, राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप और राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप जैसी प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए प्रवेश मानक निर्धारित करना एएफआई के लिए कोई नई बात नहीं है। घरेलू कैलेंडर में एएफआई आगामी सत्र में देश के विभिन्न भागों में आठ इंडियन ओपन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा जिससे कि एथलीटों को उनके मूल स्थानों के निकट अधिक अनुभव मिल सके।

ऐसी ही एक एकदिवसीय प्रतियोगिता एक अप्रैल को पंजाब के संगरूर में हुई थी जबकि फेडरेशन कप से पहले तीन और प्रतियोगिताएं पांच अप्रैल को गुजरात के नाडियाड में, 10 अप्रैल को रांची में और 15 अप्रैल को चेन्नई में होंगी। एएफआई के प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने कहा कि सभी इकाइयों और एथलीटों को तीन महीने पहले (इस बारे में) सूचित किया गया था और पिछले तीन महीने से यह वेबसाइट पर है। यह केवल यादव दिलाने के लिए एक सर्कुलर था।

उन्होंने कहा एथलीट अधिक प्रतियोगिताओं की मांग कर रहे हैं और फिर इसमें हिस्सा नहीं लेते। अभी तुर्की में ट्रेनिंग कर रहे चोपड़ा ने आश्चर्यजनक रूप से पिछले साल भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में भाग लिया था लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि वह इस साल किसी घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे या नहीं। वह तब 2021 सत्र के बाद पहली बार किसी घरेलू प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। एएफआई अधिकारी ने कहा कि नीरज इस साल किसी घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेंगे या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जनवरी में यह घोषणा की गई थी कि भारत मई में स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली एक वैश्विक भाला फेंक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जिसमें टूर्नामेंट की आयोजन टीम में चोपड़ा भी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता को विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सबेस्टियन को का समर्थन मिला है लेकिन तब से आयोजन की तिथि और स्थल के बारे में कोई अपडेट नहीं है। अगर भारत में भाला फेंक प्रतियोगिता अगले महीने के पहले हिस्से में आयोजित नहीं होती है तो 27 वर्षीय चोपड़ा 16 मई को दोहा डाइमंड लीग में अपना सत्र शुरू कर सकते हैं।

उनके एशियाई चैंपियनशिप में भाग लेने की संभावना नहीं है क्योंकि इस साल उनका मुख्य लक्ष्य 13-21 सितंबर तक तोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव करना होगा। चेन्नई में 20-24 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप भारतीय एथलीटों के लिए विश्व चैंपियनशिप के लिए पात्रता हासिल करने वाली अंतिम क्वालीफाइंग प्रतियोगिता होगी।

नए प्रारूप में होगी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप

झांसी। यहां चार से 15 अप्रैल तक होने वाली 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीन डिवीजन में 30 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र होगा। यह पहली बार होगा जब मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाने वाला पुरुष टूर्नामेंट तीन डिवीजन के नए प्रारूप में खेला जाएगा। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप मार्च में इसी तरह के नए प्रारूप में खेली गई थी। इस घरेलू प्रतियोगिता में पहली बार प्रमोशन (शीर्ष डिवीजन में जगह बनाना) और रेलीगेशन (निचले डिवीजन में खिसकना) का प्रावधान है।

यही कारण है की टीमों को तीन डिविजन ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। डिवीजन ए शीर्ष स्तर का डिवीजन होगा क्योंकि इसमें टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए अपना दावा पेश करेंगी। डिवीजन बी में टीमें अगले सत्र में डिवीजन ए में जगह बनाने के लिए, जबकि डिवीजन सी में टीमें अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में जगह हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। डिवीजन बी और सी के मैच चार अप्रैल से जबकि डिवीजन ए के मैच आठ अप्रैल से शुरू होंगे। पिछले कुछ वर्षों में टूर्नामेंट में उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर, डिवीजन ए में भारत की शीर्ष -12 टीमें हैं, जिनमें गत चैंपियन ओडिशा और उपविजेता हरियाणा शामिल हैं। डिवीजन ए में अन्य टीमें पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, हॉकी, कर्नाटक और पुडुचेरी हैं। इन टीमों को चार पूल में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने-अपने पूल में प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी से एक बार खेलेगी।

यह एकमात्र डिवीजन होगा जिसमें नॉकआउट चरण होगा। प्रत्येक पूल से शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें 12 अप्रैल को होने वाले क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफ़ाइनल 13 अप्रैल को जबकि फाइनल और तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए मैच 15 अप्रैल को खेले जाएंगे। डिवीजन ए से सबसे निचले स्थान पर रहने वाले दो टीम डिवीजन बी में खिसक जाएगी। डिवीजन बी में 10 टीमें डिवीजन ए में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टीमों को दो पूल में बांटा गया है। पूल ए में चंडीगढ़, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जबकि पूल बी में दिल्ली, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, केरल, असम शामिल हैं। डिवीजन बी से शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें अगले सत्र में डिवीजन ए में जगह बनाएंगी, जबकि निचले स्थान पर रहने वाली दो टीम डिवीजन सी में खिसक जाएंगी।

डिवीजन सी में आठ टीमें डिवीजन बी में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टीमों को दो पूल में विभाजित किया गया है। पूल ए में राजस्थान, अरुणाचल, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा जबकि पूल बी में छत्तीसगढ़, हिमाचल, बिहार और गुजरात शामिल हैं। डिवीजन सी में शीर्ष दो टीमें डिवीजन बी में जगह बनाएंगी। तीनों डिवीजन में अंक प्रणाली एक समान है। प्रत्येक टीम को जीत के लिए तीन अंक, ड्रॉ के लिए एक अंक और हार के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान नए प्रारूप ने वास्तव में अच्छा काम किया और हम राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप में इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। मुझे उम्मीद है कि टीमें मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी।

पीएम मोदी का बैंकॉक में जोरदार स्वागत, बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

बैंकॉक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज यहां थाईलैंड की राजधानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने स्वागत किया। थाईलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत कर प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार सुबह थाईलैंड के लिए रवाना हुए थे। बैंकॉक रवाना होने से पहले अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं और 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पिछले दशक में बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के साथ, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्सटेक के केंद्र में है।

मैं बिम्सटेक देशों के नेताओं से मिलने और देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा कि आधिकारिक यात्रा के दौरान मुझे थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा और थाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, जिसमें हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने की साझा इच्छा होगी, जो साझा संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिक विचारों की मजबूत नींव पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि थाईलैंड से मैं 04-06 अप्रैल तक श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। यह पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति दिसानायका की भारत की अत्यधिक सफल यात्रा के बाद है। हमें साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के संयुक्त दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा करने और हमारे साझा उद्देश्यों को साकार करने के लिए आगे मार्गदर्शन प्रदान करने का अवसर मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि ये यात्राएं अतीत की नींव पर बनेंगी और हमारे लोगों और व्यापक क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने में योगदान देंगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा (3-4 अप्रैल) पहुंचे हैं। 3 अप्रैल को गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न अपने भारतीय समकक्ष का आधिकारिक स्वागत करेंगे।

इसके बाद दोनों नेता प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में चर्चा करेंगे और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इस अवसर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उल्लेखनीय है कि बिम्सटेक का आयोजन बैंकॉक के होटल शांगरी-ला में किया गया है। इस साल सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड कर रहा है।

मांडले में भारतीय टीम बचाव कार्य के साथ स्थानीय लोगों का दिल भी जीत रही

मांडले (म्यांमा)। म्यांमा में गत शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आने और उसके बाद मदद को पहुंची भारतीय टीम विपरीत परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम तो दे ही रही है; साथ ही स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान कर उनका दिल भी जीत रही है। इसी का उदाहरण मांडले में मलबे से एक शव को निकालते समय देखने को मिला।

मलबे में फंसे शव को देखकर प्रतीत होता था कि महिला और उसका बच्चा उस समय भूकंप की चपेट में आ गए जब वे नमाज पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों ने पूर्व शाही राजधानी मांडले में स्ट्रीट 86ए के पास इस आपदा स्थल पर स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शव निकालने से कदम पीछे खींच लिए। एनडीआरएफ के एक सदस्य बताया कि लेकिन समय गुजरने के साथ ही शव सड़ने लगा था। परिजनों को एहसास हुआ कि शव को पूरी तरह से निकालने के लिए उनके पास विशेषज्ञता का अभाव है, इसलिए वे हिचकिचाने लगे। उनकी शुरुआती अनिच्छा बाद में अपील में बदल गई। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ कर्मियों ने अपना कार्य पुनः शुरू किया, महिला के शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला तथा नमाज की उसकी अंतिम मुद्रा की गरिमा को बनाए रखा। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो लोग मदद स्वीकार करने में झिझक रहे थे, अब वे आभार जताते थक नहीं रहे हैं। म्यांमा में एनडीआरएफ खोज एवं बचाव अभियान दल के उप टीम लीडर डिप्टी कमांडर कुणाल तिवारी ने बताया कि टीम को शव प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। आदम हुसैन (65) ने बताया कि भूकंप उस समय आया जब मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के अंतिम जुमे (शुक्रवार) पर अलविदा की नमाज अदा कर रहे थे। राहत और बचाव कार्यों के लिए मांडले शहर को चार सेक्टरों- अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा में बांटा गया है। स्थानीय अधिकारियों ने डेल्टा को भारत को आवंटित किया है, जबकि अन्य तीन सेक्टरों को चीन, रूस और म्यांमा अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संभाला जा रहा है। एनडीआरएफ टीम ने मांडले में आवंटित 15 कार्यस्थलों में से 11 पर अभियान शुरू किया है और अब तक लगभग 30 शवों को निकाला है। हुसैन ने कहा कि हम भारत द्वारा किए गए प्रयासों से बहुत संतुष्ट हैं। मेरी बेटी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उसका भारतीय सेना द्वारा स्थापित फील्ड अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने भावुक होकर भारतीय बचावकर्मियों की प्रशंसा की। भारतीय सेना ने शहर में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया है। इसके संचालन के पहले दो दिनों में लगभग 200 रोगियों का इलाज किया गया है, जिनमें से 34 को आगे की देखभाल के लिए भर्ती कराया गया है। साठ पैरा फील्ड अस्पताल के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने बताया कि स्थानीय लोग अस्पताल के बारे में जानने के बाद से ही यहां आ रहे हैं। भूकंप पीड़ितों के अलावा अन्य लोग भी इलाज के लिए आ रहे हैं और हम खुशी-खुशी उनका इलाज कर रहे हैं।

संक्षिप्त खबरें

यमन में संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमलों में छह लोगों की मौत: हूती विद्रोही

दुबई। यमन में हूती विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्रों में बुधवार को संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम छह लोग मारे गए। हूती विद्रोहियों की ओर से मृतकों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है और इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि, अभी तक अभियान और उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 'व्हाइट हाउस' (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को हमलों की कुल संख्या 200 से अधिक बताई है। लेविट ने कहा कि इन हमलों के परिणामस्वरूप ईरान अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया है और हमने देखा है कि उन्होंने हूती नेताओं को मार गिराया है।

म्यांमा भूकंप: मृतकों की संख्या बढ़कर 3,085 हुई

बैंकॉक। म्यांमा में करीब एक सप्ताह पहले आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 3,085 हो गई। देश की सैन्य सरकार ने यह जानकारी दी। एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि 4,715 लोग घायल हुए हैं तथा 341 लापता हैं। पिछले शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमा के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इससे कई इलाकों में हजारों इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और पुल नष्ट हो गए। स्थानीय मीडिया में हताहतों की जो संख्या बताई गई है वह आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। चूंकि दूरसंचार सेवाएं व्यापक रूप से बंद हैं तथा कई स्थानों तक पहुंचना कठिन है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसे-जैसे अधिक विवरण सामने आएगा, मृतक संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उसके प्रारंभिक आकलन के अनुसार, चार अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है जबकि 32 अस्पताल और 18 स्वास्थ्य केंद्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत का एक 'मोबाइल अस्पताल' और 'रूस-बेलारूस' का संयुक्त अस्पताल भी अब मांडले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

इजराइल के हवाई हमलों में 50 से अधिक फलस्तीनियों की मौत

दीर अल-बलाह। इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि उनका देश गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और फलस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा। गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थित खान यूनिस के अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों के शव नासेर अस्पताल ले जाए गए हैं, जिनमें से नौ एक ही परिवार के हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में पांच बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमलों के बाद बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों के शव खान यूनिस स्थित एक अस्पताल लाए गए हैं।

वहीं, गाजा पट्टी स्थित अहली अस्पताल में सात बच्चों समेत 21 लोगों के शव लाए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है।

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के 'जवाबी शुल्क' की आलोचना की

न्यूयॉर्क। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों और प्रवासी समुदाय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 'जवाबी शुल्क' को 'बिना सोचा समझा और आत्म-विनाशकारी' करार देते हुए इसकी आलोचना की है। अमेरिकी सांसदों और प्रवासी समुदाय के इन लोगों ने दोनों देशों के नेताओं से इन चुनौतियों से निपटने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का 'रियायती जवाबी शुल्क' लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा-26 प्रतिशत शुल्क लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर 'जवाबी शुल्क' लगाने की घोषणा की है। सांसदों ने यह भी कहा कि ट्रंप के 'जवाबी शुल्क' से भारतीय सामान की बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि ट्रंप का 'जवाबी शुल्क' कामकाजी परिवारों पर एक प्रकार का कर है, ताकि वह सबसे धनी अमेरिकियों के लिए करों में कटौती कर सकें। इलिनोइस से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये नवीनतम तथाकथित 'मुक्ति दिवस' शुल्क बिना सोचा समझा और आत्मघाती हैं, जो इलिनोइस को ऐसे समय में वित्तीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जब लोग पहले से ही अपने छोटे व्यवसायों को बचाए रखने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि 'जवाबी शुल्क' वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग-थलग कर देते हैं, अमेरिका के सहयोगियों को अलग-थलग कर देते हैं और उसके विरोधियों को सशक्त बनाते हैं। कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया कि वे ट्रंप से कहें कि वे देश को मंदी की ओर ले जाने से पहले अपनी 'विनाशकारी' शुल्क नीतियों को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि 'जवाबी शुल्क' की अमेरिकी अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कोई भूमिका नहीं है।

अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि 'जवाबी शुल्क' की घोषणा 'अप्रैल फूल' का मजाक नहीं है। रो खन्ना ने कहा कि ट्रंप वस्तुतः हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मुक्ति दिवस पर रातों-रात शुल्क लगा दिए, इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, कोई परामर्श नहीं किया, अमेरिकी कांग्रेस से कोई सलाह नहीं ली। इसका क्या मतलब है? कीमतें बढ़ने वाली हैं। कारों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। किराने के सामान की कीमतें बढ़ने वाली हैं। घर की मरम्मत और घर बनाने की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और पूरी तरह अनिश्चितता है।

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य डॉ. अमी बेरा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मैं यह स्पष्ट कर दूं: ये शुल्क अमेरिका को फिर से अमीर नहीं बनाएंगे। ये लागत आप पर-अमेरिकी उपभोक्ता पर-डाली जाएगी। यह कर कटौती नहीं है। यह कर वृद्धि है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत नये शुल्क की घोषणा की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कड़ी आलोचना की है। लेयेन ने कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है और इसके परिणाम 'लाखों लोगों के लिए भयंकर होंगे।

नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय वारेंट के बावजूद बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी बोला- आईसीसी से अलग होंगे हंगरी

बुडापेस्ट। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बृहस्पतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। नवंबर में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद से यह इजराइली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वह आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के 'चीफ ऑफ स्टाफ' गेरगेली गुलियास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हंगरी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होगा।

विशाखापट्टनम में शुरू हुआ भारत-अमेरिका का जल-थल अभ्यास 'टाइगर ट्राइंफ'

दोनों देशों की सेनाओं को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त जल-थल अभ्यास 'टाइगर ट्रायम्फ' विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह भारतीय नौसेना के युद्धपोत जलाश्व पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास अमेरिका-भारत के सामरिक समुद्री हितों और दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में बढ़ती निकटता को दर्शाने के लिए है। इस अभ्यास का उद्देश्य बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव गतिविधियों के दौरान आपसी सहभागिता की क्षमता को और बढ़ाना तथा सभी डोमेनों में संयुक्त परिचालन करना है।

अभ्यास का बंदरगाह चरण 07 अप्रैल तक विशाखापट्टनम में होगा, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई) कार्यक्रम जैसी प्रमुख सैन्य गतिविधियां, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रक्रियाऔर वायु, समुद्री, साइबर तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में युद्धाभ्यास शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों से दोनों देशों की सेनाओं को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और सशक्त संबंध बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सौहार्द बढ़ाने तथा व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए खेल कार्यक्रमों और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के दौरे का भी समन्वय किया जाएगा। समुद्री चरण 08-12 अप्रैल तक चलेगा, जो काकीनाडा में जल स्थलीय लैडिंग के बाद संयुक्त मानवीय राहत व चिकित्सा प्रतिक्रिया शिविर की स्थापना के साथ संपन्न होगा।

भारतीय नौसेना की ओर से भाग लेने वाली इकाइयों में लैडिंग प्लेटफॉर्म डॉक आईएनएस जलाश्व, इंटीग्रल लैडिंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, दिल्ली श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई, मगर श्रेणी के जल थल हमले वाले जहाज, दीपक श्रेणी के बेड़े के टैंकर आईएनएस शक्ति और पी-18आई लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान, एमएच-60आर हेलीकॉप्टर तथा हॉक विमान शामिल हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व एक इन्फैंट्री बटालियन समूह करेगा, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस और तीनों सेनाओं के विशेष कार्रवाई बल भी शामिल होंगे। इस अभ्यास में साइबर और अंतरिक्ष विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारतीय वायु सेना सी-130, एमआई-17 वी5 की क्षमता का प्रदर्शन करेगी और हवाई पोर्टेबल भीष्म चिकित्सा उपकरण का प्रदर्शन भी होगा।

अभ्यास में भाग लेने वाले अमेरिकी टास्क फोर्स में अमेरिकी नौसेना व्हिडबे आइलैंड-क्लास डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस कॉमस्टॉक (एलएसडी 45) शामिल होगा, जिसमें 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट व 1 लाइट आर्मर्ड रिकोनैसेंस बटालियन के अमेरिकी मरीन शामिल होंगे। साथ ही आर्ले बर्क-क्लास गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यूएसएस राल्फ जॉनसन तथा नौसेना का पी-8ए पोसाइडन विमान भी इसमें भाग लेगा। अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व एक प्लाटून, मेडिकल प्लाटून, सिविल-सैन्य संचालन केंद्र और मल्टी-डोमेन टास्क फोर्स संयुक्त सूचना प्रभाव फ्यूजन सेल करेगा।